सितंबर , 2021 वर्ष : 42 अंक : 9

www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश

सिक्यांग पेनपा छेरिंग और भारत के माननीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू।

मूल्य :10 रु , वार्षिक : 100 रु

सितंबर, 2021 वर्ष : 42 अंक : 9

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित

तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

वेबिनार में जुड़े परम पवन दलाई लामा जी

प्रधान संपादक
जमयंग दोरजी , जिगमे सुलट्रिम

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
तेनजिन पलजोर , तेनजिन जोरदेन

वितरण प्रबंधक
जामयंग छोपेल, छोन्यी छेरिंग

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

समाचार -

हमारी खुशी, हमारा स्वास्थ्य, हमारा भविष्य 1

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जीत की बधाई 2

सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग का पद पर १०० दिन पूरे करने पर तिब्बत टीवी को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार 3

सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू से शिष्टाचार मुलाकात की 4

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने तिब्बती बौद्ध विद्वान गो शेरब ग्यात्सो और रिनचेन त्सुल्ट्रिम की स्थिति के बारे में चीन से सवाल किया 5

जेल से रिहा होने के बाद आठ साल तक बीमार रहने के बाद तिब्बती लेखक का निधन 6

किंघई भूकंप के बाद पुनर्निर्माण में 'चीनी-शैली' के घरों से तिब्बतियों को डर लगता है 7

भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय की नई संशोधित हिंदी वेबसाइट लाँच 8

आईटीसीओ और तिब्बत समर्थक समूहों के प्रतिनिधिमंडल ने तवांग में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से शिष्टाचार भेंट की 9

आईटीसीओ समन्वयक और टीएसओ शिलांग ने मेघालय के मुख्य सचिव से मुलाकात की 10

समाचार -

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने ४८वें यूएनएचआरसी सत्र में चीन से तिब्बत में मानवाधिकारों का सम्मान करने का आह्वान किया 11

यूरोपीय संघ-चीन रणनीति पर यूरोपीय संसद की रिपोर्ट में तिब्बतियों के उत्पीड़न को लेकर चिंता 12

लेबर पार्टी के वार्षिक सम्मेलन २०२१ में लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय ने भाग लिया 13

तिब्बत में 'नरसंहार' का चित्रण करती है ताइपे की प्रदर्शनी 14

तिब्बती प्रतिनिधि चीन के अत्याचारों के खिलाफ बहु-सांस्कृतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए 15

चीन के शिकंजे से तिब्बत कब और कैसे मुक्त हो पाएगा?- ओप ऐड 16

भारत को अपनी तिब्बत नीति को 'मुक्त' करना चाहिए, 'दुनिया की छत' पर मानवाधिकारों के उल्लंघन को उठाना चाहिए 17

मुद्रक एवं प्रकाशक जमयांग दोरजी द्वारा प्रेम गुलाटी , डोली ऑफसेट प्रिंटर्स , डी -१५२ , एफ. एफ. सी. ओखला , नई दिल्ली -११००२० से मुद्रीत

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट www.indiatibet.net
Email: indiatibet7@gmail.com

विचार

एन.एस.वेंकटरमन

अपनी बात

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के होते भारत-चीन सीमा कहना गलत

गत 2 सितंबर, 2021 को 61 वाँ तिब्बती लोकतंत्र दिवस विश्वभर में मनाया गया। इसके लिये सभी तिब्बती और तिब्बत समर्थकों को साधुवाद। साम्राज्यवादी चीन ने लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवीय आदर्शों तथा सांस्कृति कमर्यादाओं का अतिक्रमण कर तिब्बत पर 1959 में अवैध नियंत्रण कर लिया था।पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। वह भारत एवं चीन के बीच बफर स्टेट (मध्यस्थ राज्य) था। स्वतंत्र तिब्बत पर चीन के साम्राज्यवादी नियंत्रण ने तिब्बत में अमानवीय क्रूरता शुरु करदी जो कि लगातार जारी है। हर प्रकार से तिब्बती पहचान को मिटाने की साजिश जारी है।

स्वतंत्र तिब्बत पर अवैध नियत्रंण कर के चीन ने अफवाह फैलाई कि तिब्बत कभी स्वतंत्र देश नहीं था। उसने तिब्बत को चीन का अंग बताया और कहा कि वह तिब्बत का भरपूर विकास कर रहा है। विकास के नाम पर तिब्बत की प्राकृति क संपदा की लूट होने लगी तथा वहाँ के पार्यावरण को संकट ग्रस्त कर दिया गया। चीन द्वारा तिब्बती नदियों पर बड़े-बड़े बांध बनाये जाने तथा उनकी धाराओं को मनमाने ढंग से मोड़ने के कारण तिब्बत के ग्लेसियर (हिमनद) सूखने-सिकुड़ने लगे। ग्लेसियर की अधिकता के कारण ही तिब्बत को "तीसरा ध्रुव "और" दुनिया की छत" कहा जाता है।

तिब्बती क्षेत्र में चीन सरकार द्वारा सामरिकदृष्टि से कई प्रकार के निर्माण एवं शोध किये जा रहे हैं। इन में से अधिकांश कार्य भारतीय सीमा से सटे तिब्बती क्षेत्र में हो रहे हैं। रेल, सड़क, हवाई पट्टीतथा सैनिक मोर्चों का निर्माणऐ से ही उदाहरण हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत को कमजोर तथा अपमानित करना है।तिब्बती क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के विरोध में करते हुए चीन ने 2017 में डोकलाम तथा 2020 में गलवान घाटी के संकट को पैदा किया। निकट वर्षों में वह तवांग या चमोली में भी ऐसा कर सकता है। इस से पूरा हिमालय क्षेत्र संकट ग्रस्त हो जाये गा।

चीन की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। हाल में भारतीय सीमा से सटे तिब्बती गाँवों को विकसित करने के नाम पर उन्हें सामरिक मोर्चों के रुप में बदला जा रहा है। वे गाँव नहीं रहकर सैनिक छावनी बन जायेंगे। ऐसे में भारत को भी इस से सटे अपने क्षेत्र में सैनिक तैयारी बढ़ानी होगी तथा सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी करनी होगी। भारत विरोधी गतिविधियों के लिये चीन द्वारा नेपाल का इस्तेमाल भी इसी विस्तारवादी साजिश का हिस्सा है।

परमाणु कचरे को तिब्बती भूभाग में गाड़े जा ने से भारत कोभी खतरा है। तिब्बती भूभाग से तस्करीको बढ़ावा देकर चीन भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाता है। भारत में अवैध हथियार और मुद्रा पहुँचा कर आतंकवाद एवं अलगाववाद की मदद की जार ही है। तिब्बत से सटी भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिये भारत सरकार पूर्णतः तत्पर है। फिर भी चीन के तथा कथित मित्रता पूर्ण बयानों से हमेशा सावधान रहना होगा। "पंचशील" और "हिन्दी चीनी भाई-भाई" के नारों के बीच ही चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। तब उस ने भारत के बड़े क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया था। भारतीय संसद ने 14 नवंबर, 1962 को सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर संकल्प लिया था कि हम चीन के अवैध कब्जे से भारतीय भूभाग को पूर्णतः मुक्त करायेंगे। उस संसदीय सकल्प को पूरा करने के लिये हमें तैयारी करनी है। शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में भी उस संसदीय संकल्प को प्रमुखता से छापा जाये। इस से विद्यार्थी वर्ग को परिचित रखना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इससे यह भी पता चलेगा कि चीन के साथ "अर्थहीन-अंतहीनवार्ता" की कोई जरुरत नहीं है।

भारत की राष्ट्रीय शक्ति में विस्तारही चीनी विस्तारवाद का प्रभावी जवाब है। तिब्बती लोकतंत्र दिवस के सफल आयोजन से भीभार तीय राष्ट्रीय शक्ति में विस्तार हो रहा है। तिब्बत और भारत के लिये हिमालय की सुरक्षा समान रुप से महत्वपूर्ण है। दोनों के लिये चीनी साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश आवश्यक है। संसार में अनेक देश और संगठन तिब्बती संघर्ष का समर्थन कर रहे है। उनके सहयोग से यह संघर्ष चीनी विरोध के बावजूद जारी हैं भारत भौगोलिक रुप से तिब्बत का पड़ोसी है। "भारत-तिब्बत सीमा पुलिस "इसी तथ्य का प्रमाण है कि सैंकड़ों साल से भारत की सीमा तिब्बत से जुड़ी है। भारत-चीन सीमा तिब्बत की चीनी पराधीनता का प्रतीक है।

चीन सरकार की रुचि तिब्बत मामले को उलझा ने में है। बार-बार विभिन्न संगठन मांग कर रहे हैं कि चीन सरकार लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित तिब्बत सरकार तथा दलाईलामा के प्रतिनिधियों के साथ निर्णायक वार्ता करे और "मध्यममार्ग" अपना ते हुए तिब्बतको "वास्तविक स्वायत्तता" प्रदानकरे। प्रतिरक्षा और पर राष्ट्र विषय चीन के साथ रहें तथा शेष विषय तिब्बत सरकार को सौंपे जायें। तिब्बत के प्रशासनिक स्वरुप को पूर्वव्त किया जाये। इस समय तिब्बती क्षेत्र का अंगभंग किया गया है और विश्व समुदाय की आँखों में धूल झोंकने के लिये तिब्बत को तथा कथित स्वायत्तता प्रदान की गई है। तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता ही समस्या का समाधान है। इस से तिब्बत को स्वशासन का अधिकार मिल जायेगा और चीन की एकता-अखण्डता भी सुरक्षित रहेगी। ऐसी व्यवस्था के प्रावधान चीन के संविधान और राष्ट्रीयता संबंधी कानून में ही उपलब्ध हैं।

प्रो. श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय, तिजारा (राजस्थान)
मो.-9829806065, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

• हमारी ख़ुशी, हमारा स्वास्थ्य, हमारा भविष्य

dalailama.com, २२ सितंबर, २०२१

परम पावन दलाई लामा ऑनलाइन प्रवचन के दौरान

थेकछेन छोलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत। मोनमाउथ विश्वविद्यालय, न्यू जर्सी के अध्यक्ष डॉ. पैट्रिक लेही ने २२ सितंबर की प्रातः परम पावन दलाई लामा का स्वागत करने के बाद उनसे आनंद, स्वास्थ्य, कल्याण और पृथ्वी के भविष्य के परस्पर संबंधों के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि मोनमाउथ के छात्र और शिक्षक पृथ्वी पर आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए ख़ुशहाल, स्वस्थ, अधिक करुणामय और सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित हैं। परम पावन ने शांति और आनंद के बारे में बात करने का अवसर देने के लिए पहले धन्यवाद दिया फिर इस बारे में बात की।

उन्होंने कहा, 'जाहिर है, हम सभी शांति से रहना चाहते हैं, जानवर भी शांति से रहना चाहते हैं। अगर आग लगती है तो कीड़े भी उससे बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि, जो चीज़ मनुष्य को अलग बनाती है, वह हमारे पास का अद्भुत मस्तिष्क है। हम यह सोचने में सक्षम हैं कि समस्याओं से कैसे बचा जाए और कैसे दूर किया जाए। हम आगे के बारे में भी सोच सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, 'फिर मनुष्य संकट भी पैदा करता है। हजारों वर्षों से हमने विभिन्न प्रकार के हथियारों का निर्माण किया है। हम कभी-कभी हथियारों को शांति के उपकरण के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन वास्तव में हथियार का एकमात्र उद्देश्य चोट पहुंचाना और मारना है। हथियारों के बिना दुनिया ज्यादा शांतिपूर्ण होगी।'
उन्होंने कहा, 'हम घातक से और घातक हथियारों की जटिल से जटिल प्रणालियों के निर्माण में ऊर्जा लगाते हैं और इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। फिर हम शांति की बात करते हैं। लेकिन हम इस तथ्य को नजरंदाज कर देते हैं कि वास्तविक शांति प्राप्त करने में हथियारों का कोई योगदान नहीं है।'

परम पावन ने कहा, 'हमारी दुनिया आज बहुत अधिक एक-दूसरे पर आश्रित है। अतीत में, हम केवल अपने इलाके के लोगों के बारे में ही चिंतित रहते थे। आजकल, जलवायु संकट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी नई चुनौतियां हम सभी को प्रभावित करती हैं, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के संचालन में हमें पूरी मानवता को ध्यान में रखना चाहिए होता है।'

उन्होंने आगे कहा कि जहां तक हथियारों के निर्माण और बिक्री का संबंध है, हमें बस इतना कहना चाहिए कि 'अब बस करो।' हमारा लक्ष्य एक सैन्यविहीन दुनिया में वास्तविक शांति प्राप्त करने का होना चाहिए। इस ग्रह पर मनुष्य के रूप में, हमें मानवता की एकता पर विचार करना होगा। हम सभी को एक साथ शांति और सद्भाव से रहने की जरूरत है। हथियारों के उत्पादन और बिक्री का इसमें कोई योगदान नहीं है।

उन्होंने कहा कि वास्तविक विश्व शांति मन की शांति पाने में निहित है। क्रोध, ईर्ष्या और हताशा आसानी से हिंसा का स्रोत बन जाते हैं। इसलिए हमें करुणा की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है जो कि हमारा मूल मानव स्वभाव है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अतीत में हमने वास्तव में केवल अपने स्थानीय समुदाय पर ध्यान दिया है, जबकि अब हमें पूरी मानवता को ध्यान में रखना है।
परम पावन ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'हमें मन की शांति पाने पर ध्यान देना चाहिए, यह याद रखना चाहिए कि करुणा वास्तविक शांति की नींव है। मनुष्य के रूप में, हमारे पास एक ही तरह का चेहरा और एक ही तरह का दिमाग है। क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ समान है, हमें एक शांतिपूर्ण, सुखी दुनिया में साथ-साथ रहने का रास्ता खोजना होगा।'

उन्होंने कहा, 'मैं मानता हूं कि जब मैं तिब्बत में रहता था, तिब्बती लोग मेरी सबसे बड़ी चिंता थे। हालांकि, निर्वासन में आने के बाद से मुझे व्यापक दुनिया का पता चला है। मनुष्य हर जगह भाई-बहन के समान है। जब मैं अन्य लोगों से मिलता हूं, जहां भी हूं, मैं मुस्कुराता हूं और अधिकतर लोग भी वापस मुस्कुराते हैं। यही मानव भाई-बहन करते हैं। अन्य लोग भी मेरे जैसे ही इंसान हैं। राष्ट्रीयता, नस्ल और धार्मिक आस्था के अंतर तुलनात्मक रूप से गौण महत्व के हैं।'
'आज सुबह मेरे तिब्बती और एलोपैथिक चिकित्सकों ने मेरी एक संक्षिप्त चिकित्सा जांच की। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। मेरा मानना है कि इसका एक बड़ा कारण है कि मेरा मन शांत है। लगातार क्रोध और भय हमारे स्वास्थ्य को बाधित करते हैं, जबकि मन की शांति सेहत को सामान्य करने की दिशा को बढ़ावा देने में बहुत मदद करती है।'
'कभी-कभी शांति की तलाश में लोग ट्रैंक्विलाइज़र लेते हैं। मैंने कभी नहीं लिया। मैं मन की शांति पैदा करने के लिए काम करता हूं और देखता हूं कि मुझे नौ घंटे की नींद आती है। मेरे अनुभव में, करुणा के लिए की जानेवाली कोशिशें सुनिश्चित करती है कि मैं अच्छी तरह सो जाऊं, अच्छी भूख लगे और अच्छा पाचन हो।'

'भाइयों और बहनों, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं, जिसे मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं।'

परम पावन से मोनमाउथ विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों की ओर से अनेक प्रश्न पूछे गए। उन्होंने स्वीकार किया कि हम वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। जैसे-जैसे सूरज की गर्मी के सामने हमारा सुरक्षा कवच कमजोर होता जा रहा है, दुनिया गर्म होती जा रही है और जलवायु बदल रही है। नतीजतन, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। हम अपने जीवन स्तर को बदल कर जलवायु परिस्थितियों को स्थिर कर सकते हैं।
परम पावन ने जलवायु परिवर्तन के खतरों का चित्रण करते हुए तिब्बत का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि तिब्बती पठार एशिया की प्रमुख नदियों का स्रोत है और ये नदियां करोड़ों लोगों को जल की आपूर्ति करती हैं। अगर हम इन नदियों की रक्षा नहीं कर पाए तो क्या होगा, यह कोई नहीं जानता।

परम पावन ने कहा कि कोविड-१९ महामारी ने दुनिया के बड़े हिस्से में संकट पैदा किया है और हमें अपनी सुरक्षा के लिए शारीरिक और मानसिक स्तर पर सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने शांतिदेव की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह का हवाला देते हुए कहा कि हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्या हमारे सामने आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो हमें उन उपायों को करने की जरूरत है। यदि वे हमारे नियंत्रण से बाहर हैं तो हमें बस इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है; इसके बारे में चिंता करने से मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय सलाह का पालन करना महत्वपूर्ण है।
परम पावन ने स्पष्ट किया कि बौद्ध दर्शन धर्म चित्त की शांति के महत्व पर बल देता है। व्यक्ति स्थिर चित्त और प्रसन्न रहने के लिए प्रशिक्षण लेता है। इसके बाद वह ख़ुद से सीखी हुई बातों को दूसरों को भी सिखाने में सक्षम हो पाता है। उन्होंने कहा कि

बुद्ध ने पहले खुद ज्ञान प्राप्त किया और फिर अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को शिक्षा दी। अगर एक व्यक्ति के रूप में हम खुद को बेहतर बनाने, अधिक अनुशासित और खुश रखने में सक्षम हैं तो हम दूसरों के लिए भी लाभकारी हो सकेंगे।

लोग चाहे दुनिया में कहीं भी पैदा हुए हों, इंसान के तौर पर वे एक जैसे होते हैं। वे एक ही तरह से पैदा होते हैं और एक ही तरह से अपनी मां की देखरेख में बड़े होते हैं। सांस्कृतिक विरासत और जीवन के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मौलिक रूप से मनुष्य के रूप में हम सभी समान हैं। परम पावन ने आगे कहा कि अतीत में अमेरिका में रंग के आधार पर लोगों का विभाजित किया गया था। लेकिन अब हमें नहीं लगता कि रंग हमें विभाजित करने का आधार है, चाहे हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम कहीं से भी आए हों या हम किसी भी धर्म का पालन करते हों। इसके बजाय हमें उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो हमें मनुष्य के रूप में समान बनाती है।

परम पावन ने टिप्पणी की, 'अफ्रीका में बिशप डेसमंड टूटू, नेल्सन मंडेला मेरे अच्छे मित्र हैं और हमारे शरीर का रंग अलग तरह का हैं, लेकिन जब हम मुस्कुराते हैं, तो हम एक सामान्य मानवीय आनंद प्रकट करते हैं।'

उन्होंने कहा कि एक बच्चे को सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण बात सौहार्दपूर्ण होना है। स्कूलों में इसके लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। फिर भी यह स्पष्ट है कि छात्र उन शिक्षकों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जो मुस्कुराते हैं और गर्मजोशी से जवाब देते हैं। परम पावन ने उल्लेख किया कि बचपन में उनके शिक्षक कठोर होने के बजाय हंसमुख और खुले रहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बचपन में खुशी महसूस की है।

यह पूछे जाने पर कि दुख को कैसे दूर किया जाए और आंतरिक शांति कैसे प्राप्त की जाए, परम पावन ने उत्तर दिया कि दुख जीवन का हिस्सा है। उन्होंने सलाह दी कि मुसीबत का सामना करने पर इसलिए चिंता को कम करने के तरीके खोजने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। चूंकि युवा अधिक अधीर होते हैं, इसलिए उनके बुजुर्ग उन्हें धैर्य रखने की सलाह दे सकते हैं। परम पावन ने कहा कि नकारात्मक अनुभवों का सामना करने से सीखने में सहायता मिलती है और यह प्रक्रिया आंतरिक शक्ति के विकास की ओर ले जाती है।

उन्होंने कहा, 'जब से मैं शरणार्थी बना हूं, मैं और लोगों को यह सीख देने में सक्षम हो गया हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को मन की शांति विकसित करने के अवसरों में कैसे बदला जाए।'

मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। देर-सबेर हम सभी को मरना ही है और जब वह समय आए तो मन की शांति का होना जरूरी है। परम पावन ने बताया कि कैसे सूक्ष्मतम मन शाश्वत है। उन्होंने कहा कि एक बच्चे के पैदा होने की अवधारणा केवल भौतिक तत्वों, शुक्राणु और डिंब की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती है। उन्होंने कहा कि गर्भ में बच्चे का आगमन तभी होता है जब ये तत्व चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। परम पावन ने इस मुद्दे को छुआ कि कैसे मानसिक चेतना की निरंतरता जीवन को रेखांकित करती है। उन्होंने उन बच्चों का हवाला दिया जिन्हें अपने पिछले जन्मों की बातें याद हो आती हैं। उन्होंने 'थुकदम' घटना की ओर इशारा किया जो तब होता है जब कुछ लोग मर जाते हैं लेकिन उनके शरीर कुछ समय के लिए ताजा रहते हैं क्योंकि उनका सूक्ष्मतम दिमाग मौजूद रहता है।

एक प्रश्नकर्ता जानना चाहते थे कि निराशा की भावनाओं से कैसे निपटा जाए। इस पर परम पावन ने सुझाव दिया कि यदि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति केवल भौतिक चीजों में रुचि रखता है तो वे आशा खो सकते हैं। लेकिन, अगर उन्हें मन की कुछ समझ है और वे आंतरिक शांति के लिए काम करते हैं तो वे समाधान ढूंढ लेंगे।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का उद्भव इस बात का प्रतिबिंब है कि चीजें कैसे बदलती हैं। परम पावन ने कहा कि अतीत में हम दुनिया में सोशल मीडिया की इस तरह की प्रवृत्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब, जब हमें पूरी मानवता की चिंता करने की जरूरत पड़ी है तो हमारे पास मदद करने के लिए सुविधाएं भी आ गई हैं। हमारे पास युवाओं को बल के उपयोग की अतिरेकता और सैन्यविहीन दुनिया बनाने की महत्ता जैसे नए तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के अवसर हैं।

जरूरी नहीं कि आज के युवाओं को वही दोहराने की कोशिश करनी चाहिए जो पहले हुआ करता था। बेहतर होगा कि वे बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल नई सोच विकसित करें। इसे पूरा करने का एक तरीका अधिक करुणाशील समाज के निर्माण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी को चिह्नित करना है।

बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए परम पावन ने कहा कि बुद्ध के सिद्धांत का आधार चार आर्य सत्य हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि आठ अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि आर्य सत्यों के लिए ये अष्टांगिक मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण हैं। दुख और उसके मूल की सत्यता स्पष्ट है, जबकि तीसरा सत्य यह है कि दुखों और उसके कारणों का निवारण किया जा सकता है और यही सत्य आशा प्रदान करता है। यही सत्य अष्टांगिक मार्ग की साधना में रत होने का उत्साह प्रदान करता है।

'कांफ्रेंस सर्विसेज' की निदेशक लू-एन रसेल ने परम पावन की टीम के सदस्यों को धन्यवाद देने के साथ सत्र का समापन किया, जिन्होंने इस अवसर को सुगम बनाया था। उन्होंने परम पावन को उनके स्नेहपूर्ण और करुणामय मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके शब्दों ने उनके प्रत्येक श्रोता को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने परम पावन से कहा, 'आपने हम सभी पर जो प्रभाव डाला है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करती हूं कि हमारा सहयोग और निरंतर प्रयास आने वाले दिनों में एक साथ आगे बढ़ता रहे।'

• कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जीत की बधाई

dalailama.com २२ सितंबर, २०२१

थेकछेन छोलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत। परम पावन दलाई लामा ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को वहां के राष्ट्रीय चुनावों में उनकी पार्टी की जीत के लिए पत्र लिखकर बधाई दी।

उन्होंने लिखा, 'मैं कोविड-१९ महामारी जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपके द्वारा दिखाए गए साहसिक नेतृत्व की सराहना करता हूं, जिसने दुनिया भर में इतने सारे लोगों को प्रभावित किया है। मैंने लंबे समय से कनाडा की इस नीति की प्रशंसा की है, जिसमें मानवीय आधार पर दुनिया के अशांत इलाकों के कमजोर और पीड़ित लोगों को अनुकंपा के आधार पर अपने यहां स्वागत किया जाता है। एक मानद कनाडाई नागरिक के रूप में मुझे इस तरह के उदार, मानवीय मूल्यों पर गर्व महसूस होता है।'

'इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि बीते वर्षों में मैने अनेक बार कनाडा का दौरा किया है। कनाडा के मेरे भाइयों और बहनों ने मेरे प्रति जो मित्रता और स्नेह दिखाया है, उसने मेरे अंतर्मन को गहराई तक प्रभावित किया है। कनाडा ने आपके पिता के प्रधानमंत्रित्व काल से ही तिब्बती शरणार्थियों का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, उसके लिए मैं इस अवसर पर आभार प्रकट करता हैं। मैं समझता हूं कि कुल

मिलाकर तिब्बती लोग कनाडा के बहुसांस्कृतिक समाज में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं।'

परम पावन ने कनाडा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में ट्रूडो को सफलता मिले, इसके लिए प्रार्थना की और शुभकामनाएं देते हुए अपना पत्र समाप्त किया।

• सिक्योंग पेनपा छेरिंग का पद पर १०० दिन पूरे करने पर तिब्बत टीवी को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार

tibet.net, ०४ सितंबर २०२१

धर्मशाला। गत २७ मई को सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग द्वारा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कार्यकारी प्रमुख (सिक्योंग) की जिम्मेदारी संभालने के बाद ३ सितंबरको उनके कार्यकाल के १०० दिन पूरे हो गए।

कार्यालय में अपने १०० दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने तिब्बत टीवी की होस्ट तेनज़िन चेमे को विशेष साक्षात्कार दिया। ३० मिनटलंबे साक्षात्कार में सिक्योंग ने पिछले १०० दिनों में अपने प्रशासन द्वारा किए गए मुख्य कार्यों, निर्वासित तिब्बतियों के समग्र कल्याण के लिए अपनी प्रशासनिक नीति और अन्य बातों के अलावा चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए अपनी राजनीतिक रणनीतियों के बारे में बातें कीं।

तेनज़िन चेमे: आपने सिक्योंग के रूप में कार्यालय में १०० दिन पूरे कर लिए हैं। क्या मैं सबसे पहले यह सवाल पूछ सकती हूं कि जब आपने पहली बार कार्यालय की जिम्मेदारी संभाली, तब से अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा है?

सिक्योंग: जहां तक पिछले १०० दिनों से प्रशासन का नेतृत्व करने वाली मेरी आकांक्षाओं और दूरदर्शिता का संबंध है, मैं सकारात्मक रूप से पुष्टि कर सकता हूं कि वर्तमान कशाग मेरे अभियान घोषणापत्र में उल्लिखित वादों के अनुसार बिना किसी लापरवाही के सुचारू रूप से काम कर रहा है।

तेनज़िन चेमे: आपने कई मौकों पर कहा है कि आपका प्राथमिक प्रयास लंबे समय से चली आ रही तिब्बत समस्या को हल करने की दिशा में होगा। इसे हासिल करने के लिए आपने किस तरह की रणनीति और नीतियों की योजना बनाई है?

सिक्योंग: उनमें से प्रत्येक को विस्तार से सूचीबद्ध करना मुश्किल है। लेकिन मैंने कई मौकों पर कई बार कहा है कि मैं और वर्तमान कशाग चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए अहिंसा और मध्यम मार्ग दृष्टिकोण पर आधारित नीतियों के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाएंगे और प्रयास करेंगे। परम पावन दलाई लामा द्वारा समर्थित मध्यम मार्ग दृष्टिकोण को निर्वासित तिब्बती संसद का पूरा समर्थन प्राप्त है और तिब्बतियों को इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है।

चीन-तिब्बत वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए मैंने जो पहला कदम उठाया, वह चीन-तिब्बत वार्ता पर मौजूदा टास्क फोर्स को भंग करना और इसे एक समिति के तौर पर पुनर्गठित करना रहा है। पिछली समिति के सभी सदस्यों ने सराहनीय कार्य किया है और उनमें से प्रत्येक की इसके लिए मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि मैंने जो बदलाव किए हैं वे जरूरी थे। जैसे, नई समिति में चार सदस्य होंगे जो सीटीए के प्रत्येक विशिष्ट विभाग से एक सदस्य होंगे, जो इसके कार्य से संबंधित होंगे। सुरक्षा विभाग को इसके प्राथमिक कार्यों के अलावा तिब्बत के अंदर की प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। इसी तरह, सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग दुनिया भर से तिब्बत संबंधी समाचारों को इकट्ठा करेगा और सीटीए के तिब्बत नीति संस्थान (टीपीआई) को सुरक्षा विभाग और डीआईआईआर द्वारा एकत्र की गई जानकारी पर विश्लेषणात्मक शोध करने के लिए कहा गया है। इसी तरह, एक राजनीतिक सचिव नियुक्त किया गया है जो बाकी सदस्यों के साथ समिति का नेतृत्व करेगा।

सदस्य सौंपे गए संबंधित कार्यों पर अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करेंगे और इस बारे में राय देंगे कि एकत्रित जानकारी का उचित उपयोग कैसे करें। जब तक चीन-तिब्बत संघर्ष का समाधान नहीं हो जाता, तब तक टास्क फोर्स तिब्बत के अंदर की वास्तविक स्थिति को उजागर करने और तिब्बत के बारे में चीन के मनगढ़ंत और विकृत आख्यान को वैश्विक समुदाय में उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध होगी।

इसी तरह, बड़ी संख्या में तिब्बती इन दिनों पश्चिमी समुदायों में घुलमिल गए हैं। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त की है, विभिन्न भाषाओं को जानते हैं और अपने मेजबान राष्ट्रों की प्रणाली के आदी हो गए हैं। ये ऐसी क्षमताएं हैं जिनका प्रभावी और तर्कसंगत रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

एक राष्ट्र के विकास के लिए युवा नेतृत्व के महत्व को स्वीकार करते हुए वर्तमान प्रशासन कई कार्यक्रमों और पहलों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कार्यक्रम और पहलें तिब्बत मुक्ति साधना में अधिकतम युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगी।

अगले साल से विभिन्न देशों में स्थापित 'तिब्बत कार्यालय' मेजबान देश की सरकार, संसद, थिंक टैंक, मीडिया हाउस और तिब्बत समर्थक समूहों संपर्कों को बढ़ाएंगे। जहां तक तिब्बती समुदायों और तिब्बती संघों के साथ समन्वय स्थापित करने का संबंध है, मैं एक लोकपाल नियुक्त करने की सोच रहा हूं। उदाहरण के लिए, तिब्बती युवाओं के नेतृत्व में एक प्रभावी 'अंतरराष्ट्रीय समर्थन अभियान' शुरू करने के लिए हमें धन की आवश्यकता है। इसके लिए मैं तिब्बती संघों, तिब्बत समर्थक समूहों, संसदीय तिब्बत समर्थक समूहों और तिब्बत के कार्यालयों से ठोस समर्थन मांगने के बारे में सोच रहा हूं। मैं इस बारे में अगले एक या दो महीने में घोषणा कर दूंगा।

तेनज़िन चेमे: अपनी हाल की घोषणा में आपने चीन-तिब्बत वार्ता पर टास्क फोर्स को भंग कर दिया है और इसे एक नई स्थायी रणनीति समिति के साथ बदल दिया है। क्या समिति के नाम में परिवर्तन से समिति की मुख्य गतिविधियों और उद्देश्यों में कोई परिवर्तन होगा? इसके अलावा, चीन-तिब्बत वार्ता २०१०से यानि ११ वर्षों से अधिक समय से रुकी हुई है। वार्ता प्रक्रिया को फिर से शुरू करने में चीनी पक्ष से हमें क्या उम्मीद है?यदि वार्ता फिर से शुरू होती है तो चीनियों के साथ बातचीत करने के लिए तिब्बती दूत के रूप में कौन जाएंगे?

सिक्योंग: हमें सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहना चाहिए। उम्मीद बनाए रखे बिना हमारा संघर्ष भटक जाएगा। इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर रहा हूं और मैं अभी भी परिणाम को लेकर काफी आशान्वित हूं। सबसे पहले, चीनी सरकार को तिब्बत मुद्दे को उग्यूर, मंगोल और हांगकांग के संघर्षों जैसे अन्य मुद्दों के साथ देखना चाहिए। अगर उनमें राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो वे इसे आसानी से सुलझा सकते हैं।

हमें वास्तव में बातचीत के मुद्दे पर चीनी पक्ष से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, मैं सतर्क हूं क्योंकि हमें यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि क्या ये संकेत वास्तविक और भरोसेमंद हैं। यह स्पष्ट है कि चीनी सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू किए बिना हम चीन-तिब्बत संघर्ष को बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते। साथ ही जब तक चीन-तिब्बत संघर्ष का समाधान नहीं हो जाता, हम तिब्बत के भीतर तिब्बती लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में तिब्बत के अंदर की स्थिति को उजागर करने और उसकी निगरानी करने के अपने प्रयास जारी रखेंगे। निश्चिंत रहें हम चीन सरकार पर दबाव बनाने में पूरी ताकत लगा देंगे और हम इसके लिए तैयार हैं।

दूत की नियुक्ति के संबंध में हमें यह महसूस करना चाहिए कि परम पावन दलाई लामा की दृष्टि और आकांक्षा को पूरा करने के लिए चीन-तिब्बती वार्ता के दूत को सबसे पहले काम करना चाहिए। वार्ता प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के संबंध में चीनी सरकार की प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह तय किया जाएगा कि दूत की नियुक्ति कब और कैसे की जाए।

तेनज़िन चेमे: पिछले कुछ वर्षों में चीनी सरकार की आक्रामक कूटनीति और कोविड-१९ महामारी के कारण कई देशों में चीन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। उदाहरण के लिए हमारे मेजबान देश भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने परम पावन दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर सार्वजनिक रूप से बधाई दी है। तिब्बत मुद्दे पर सार्वजनिक और मीडिया चर्चाओं में भी नाटकीय बदलाव हुआ है। तिब्बती मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए हम इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं?

सिक्योंग: तिब्बत के हित के सबसे मजबूत समर्थक भारत और अमेरिकी सरकार हैं। इस बारे में विस्तार में न जाते हुए मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि भारत और अमेरिकी सरकार के साथ हमारे संबंध मजबूत और फलदायक बने हुए हैं। यदि अमेरिकी सरकार जल्द ही तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त कर सकती है, तो मेरे पास बहुत सी योजनाएं हैं जिन पर मैं संबंधित अधिकारी के साथ चर्चा और पहल करना चाहता हूं।

भारत और अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी चीन के प्रति नजरिया तेजी से बदल रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपना ध्यान यूरोपीय क्षेत्रों पर भी केंद्रित करें। इस कारण से मैं अक्तूबर में यूरोप जाने की योजना बना रहा हूं। इसी तरह यदि अमेरिका तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त करने में सक्षम होता है तो मैं भी अमेरिका का दौरा करुंगा।

यदि हम भू-राजनीतिक स्थिति में बदलाव के कारण हमें मिले इस अवसर को हासिल करने में सक्षम नहीं होते हैं तो यह तिब्बती आंदोलन के लिए ऐतिहासिक क्षति होगी। जैसा कि उदाहरण के लिए आपने पहले कहा था कि भारत में तिब्बत की स्थिति पर अभूतपूर्व रुचि विकसित हुई है और इस मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है। यह मेरे प्रयासों का परिणाम नहीं है। यह उभरी भू-राजनीतिक प्रवृत्ति का परिणाम है, जिसके कारण मुझे विभिन्न भारतीय मीडिया घरानों से बात करने का अवसर मिला। विश्व में चीन के संबंध में भू-राजनीतिक स्थिति हम तिब्बतियों के लिए तिब्बत के लिए समर्थन प्राप्त करने का एक अनूठा और सुविधाजनक अवसर प्रदान करती है। हमें यह मौका नहीं गंवाना चाहिए।

आम तौर पर बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। तिब्बती अब दुनिया भर के कई देशों में रह रहे हैं। इसलिए, इस तथ्य का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, हम जल्द ही कुछ महीनों में एक घोषणा करने जा रहे हैं ताकि दुनिया भर के तिब्बतियों से युवा पीढ़ी के नेतृत्व में तिब्बत मुक्ति साधना में भाग लेने का आग्रह किया जा सके। यदि हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो हमारी हिमायत और हमारे लॉबिंग अभियान पिछली उपलब्धियों से बहुत आगे बढ़ जाएंगे।

इसी तरह, विदेशों में स्थित तिब्बत कार्यालय (ओओटी) और उसकी गतिविधियों में भी थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है। शायद इस साल नहीं, लेकिन अगले साल से तिब्बत कार्यालयों की मुख्य भूमिका मेजबान देश की सरकार, संसद, गैर सरकारी संगठनों, थिंक टैंक, मीडिया घरानों और देश में स्थित तिब्बत समर्थक समूहों तक पहुंचने की होगी। यह ओओटी की मुख्य जिम्मेदारी होंगी। तिब्बती समुदाय और तिब्बती संघों तक पहुंचने और उनके साथ समन्वय करने के लिए हम कुछ और सोचेंगे।

तिब्बती संसद का सत्र आयोजित न हो पाना भी हमारे लिए एक छोटी सी बाधा है। इसलिए, हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे को तेजी से सुलझाया जाएगा। कशाग गतिरोध को दूर करने के लिए हरसंभव तरीके से सहायता और सहयोग देगा। हालांकि, कशाग सभी पक्षों की मंजूरी के बिना हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध बात हो जाएगी। फिर भी, यह हमारी आशा है कि संसद पहले एक सत्र आयोजित करे और गतिरोध को हल करे और फिर हम अपने आंतरिक मुद्दों के साथ-साथ अपने सामान्य मुद्दों पर भी चर्चा कर सकें। यदि इसका समाधान हो जाता है तो हम केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सामान्य कामकाज शुरू कर सकते हैं। मैंने सिक्योंग की भूमिका ग्रहण करने से पहले ही कहा था कि मैं तिब्बती सर्वोच्च न्याय आयोग के साथ-साथ तिब्बती संसद से संपर्क करुंगा ताकि उन्हें अपनी नीतियों और उद्देश्यों के बारे में सूचित किया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो सके कि हम एक-दूसरे के प्रयासों और गतिविधियों को कैसे बढ़ा सकते हैं। तिब्बती संसद के मामले में मैंने पहले ही एक योजना तैयार कर ली है कि कैसे कशाग तिब्बती संसद को अपना समर्थन देगा और हम अपने प्रयासों में सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं। मैं इसे इस साल मई के अंत या जून की शुरुआत में तिब्बती संसद में प्रस्तुत करने की योजना बना रहा था। हालांकि, वर्तमान गतिरोध और संसद द्वारा अपना सत्र आहूत करने की असमर्थता के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं पहले ही तीनों स्वायत्त निकायों के प्रमुखों से मिल चुका हूं। कुछ को छोड़कर, मैंने सभी तिब्बती गैर सरकारी संगठनों और तिब्बती मीडिया के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। ये सब कशाग के उद्देश्यों को प्रचारित करने और हम भविष्य में एक साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, को लेकर किया गया है। हर कोई हमारे प्रयासों और उद्देश्यों से प्रसन्न भी दिख रहा है। स्वतंत्रता और मध्यम मार्ग दृष्टिकोण जैसे मुद्दों पर भी मैंने तिब्बती युवा कांग्रेस के प्रमुखों से कहा कि उन्हें सबसे पहले परम पावन दलाई लामा के दृष्टिकोण, सीटीए की नीति और एमडब्ल्यूए के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करना परस्पर लाभकारी होगा। उसके बाद, वे अपने स्वयं के संगठन के उद्देश्य के बारे में बात कर सकते हैं ताकि पता चले कि संगठन उस विशेष उद्देश्य का पालन क्यों करता है। यदि वे ऐसा करते हैं तो यह हमारे समर्थकों को मिश्रित संदेश (विरोधाभासी संदेश) नहीं देगा, बल्कि उल्टे मुद्दे को स्पष्ट करने में मदद करेगा। हमें आपस में बहस करने की भी जरूरत नहीं है। यही मैंने उन्हें बताया और वे भी मान रहे हैं। अगर हम सब ऐसा सोच सकते हैं तो हमें रंगजेन और उमा (स्वतंत्रता और एमडब्ल्यूए) के बारे में अब और झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, बात यह है कि, हमारे छोटे तिब्बती समुदाय में, हम क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद के शिकार हैं जो समय के साथ बड़ा और छोटा हो जाता है। फिलहाल यह और बड़ा होता दिख रहा है।

मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में असहमति होना लाजमी है। हालांकि, साथ ही हमें यह महसूस करना चाहिए कि चीनी सरकार हम सबकी दुश्मन है, न कि हम आपस में एक-दूसरे के दुश्मन हैं। निर्वासित समुदाय में आपस में बहस करने के बजाय, हमें तिब्बत के भीतर हो रहे विकास का अध्ययन करना चाहिए जैसे कि तिब्बती क्षेत्रों में चीनियों का बड़े पैमाने पर घुसपैठ और फिर तिब्बती संस्कृति, भाषा, पर्यावरण आदि के संरक्षण के माध्यम से तिब्बती अस्मिता को संरक्षित करने का प्रयास आदि।

यदि हम इन मामलों के बारे में सोचते हैं तो हम महसूस करेंगे कि हम एक महत्वपूर्ण समय से गुज़र रहे हैं जहां हमें तत्काल तिब्बत में अपनी नीतियों के बारे में चीन पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। चीन पर दबाव बनाने का समय वास्तव में ज्वलंत स्तर पर पहुंच गया है और हमें अपने प्रयासों को फिर से मजबूत करने की जरूरत है। अपनी पहले से ही सीमित क्षमताओं को आंतरिक कलह में नष्ट करके हम न केवल तिब्बती आंदोलन में बाधा डाल रहे हैं बल्कि परम पावन दलाई लामा द्वारा हमें सौंपी गई जिम्मेदारी और विश्वास के साथ भी घात कर रहे हैं। यह हम पर एक काला धब्बा होगा जिसे हमें ऐतिहासिक रूप से ढोते रहना होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो वाकई शर्मनाक है। इस कारण से मैं प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं।

वर्तमान राजनीतिक गतिरोध हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। मैंने इसे अलग नहीं किया है और न ही मैं इसके प्रति उदासीन हूं। मैं मामले पर पूरा ध्यान दे रहा हूं। हालांकि, हमारी प्रणाली परम पावन दलाई लामा द्वारा हमें उपहार में दी गई एक लोकतांत्रिक राजनीति है। ५० से अधिक वर्षों से परम पावन ने तिब्बती राजनीति को एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में विकसित किया है, जिसे हम अभी देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। हालांकि, यदि हम नियमों और विनियमों को अलग रखते हैं और केवल कच्ची भावनाओं के आधार पर काम करते हैं, तो हमारा लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र नहीं होगा। नाम से ही लोकतंत्र होगा। हालांकि, मैं इस बात को लेकर दृढ़विश्वासी हूं कि गतिरोध के बारे में सभी पक्ष सोचेंगे और महसूस करेंगे कि प्रशासन के सुचारू कामकाज के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं।

तेनज़िन चेमे: निर्वासित तिब्बती स्कूलों और मठों में तिब्बती छात्रों और तिब्बती भिक्षुओं की घटती संख्या का सामना करना पड़ रहा है। हमें निर्वासन में तिब्बती बस्तियों के निर्वाह के बारे में भी सोचना होगा। इन मुद्दों के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?

सिक्योंग: हमने शिक्षा विभाग के साथ कई बैठकें की हैं। अब तक २५ तिब्बती स्कूलों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत किया जा चुका है। अब उत्तर भारत के छह स्कूल बचे हैं, जिनको शिक्षा विभाग के अधीन करना बाकी है। अभी कुछ हफ्ते पहले हमने शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी सेटलमेंट अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे तीन साल तक के सभी बच्चों की सूची बनाने को कहा। हमारे पास पहले से ही किंडरगार्टन और के १२ स्कूलों में नामांकित बच्चों के बारे में आंकड़े है। हमें जो आंकड़ा मिला है, उसके आधार पर यह जानना वाकई चौंकाने वाला है कि २०१२ और २०२१ के बीच इन स्कूलों में तिब्बती छात्रों की संख्या में भारी कमी आई है। २०१२ में तिब्बती स्कूलों में २०,००० से अधिक तिब्बती छात्र थे। जबकि, २०२१ में तिब्बती स्कूलों में केवल ९७०० तिब्बती छात्र हैं। तिब्बती छात्रों की संख्या में ५०% से अधिक की कमी आई है। इस कमी के कई कारण हो सकते हैं। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक तिब्बत से आने वाले तिब्बतियों के प्रवाह में विशेष रूप से २००८ के बाद से कमी है। फिर २०१३-१४ से प्रवाह और भी कम होकर १०० लोगों से भी कम हो गया। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष तिब्बत से निर्वासन में आने वाले केवल पांच लोग थे। और इस साल सिर्फ सात लोग ही निर्वासन में आए हैं। यह तिब्बती स्कूलों में तिब्बती छात्रों की कमी के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। दूसरे, कई तिब्बती भी दूसरे देशों में प्रवास कर रहे हैं। कुछ तिब्बती भारत के बड़े शहरों में भी प्रवास कर रहे हैं और वहां के स्कूलों में जा रहे हैं। इसलिए, हमें यह सोचना होगा कि स्कूलों का विलय कैसे किया जाए। मैं ०७ सितंबर से अगले कुछ दिनों में उन पांच स्कूलों का दौरा करुंगा जिनको शिक्षा विभाग के अधीन किया जाना शेष है। लद्दाख से धर्मशाला वापस जाते समय मैं डलहौजी में स्कूल और बस्ती देखने के लिए रुका था। डलहौजी के स्कूल में केवल २२ छात्र थे। इन २२ छात्रों में से तीन कारगिल के लद्दाखी थे। शेष १९ स्थानीय भारतीय थे। वहीं २२ छात्रों के लिए स्कूल में प्रिंसिपल समेत १५ स्टाफ और टीचर हैं। यही जमीनी हकीकत है। शिमला में तिब्बती स्कूल में ९०% छात्र तिब्बती समुदाय से जबकि १०% छात्र स्थानीय समुदाय से होना चाहिए। हालांकि, आज यह स्थानीय समुदाय से ९०% और तिब्बती समुदाय से १०% छात्र है। हरबर्टपुर और सीएसटी मसूरी में भी यही स्थिति है। और ऐसी स्थिति कई स्कूलों में है। टीसीवी के मामले में इसमें सिर्फ इसके तहत आने वाले स्कूलों की जानकारी होती है। इसी तरह, संभूता के पास केवल अपने स्वयं के स्कूलों के बारे में जानकारी है। तिब्बती स्कूलों और छात्रों के बारे में किसी के पास पूरा आंकड़ा नहीं है। टीएचएफ मसूरी के साथ भी ऐसा ही है। धोंडुपलिंग और देहरादून के आसपास के अन्य क्षेत्रों में कुछ तिब्बती निजी स्कूल भी हैं जैसे लिंगत्संग बस्ती। हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। इसलिए भविष्य के लिए योजना तैयार करने के लिए हम निकट भविष्य में सभी स्कूल प्रमुखों की एक बैठक करेंगे, चाहे उस स्कूल का विलय होना हो या एक-दूसरे को सहायता प्रदान करना हो। हालांकि, हमारा प्राथमिक उद्देश्य तिब्बती बच्चों की शिक्षा है।

जहां तक तिब्बती बस्तियों का संबंध है, भारत में लगभग ४५ तिब्बती बस्तियां हैं। नेपाल में १२-१३ और भूटान में ६-७ बस्तियां हैं। हमें भविष्य में इन बस्तियों की स्थिरता का आकलन करना होगा। विशेष रूप से उन छोटी बस्तियों को, जिनके जीवित रहने की संभावना कम है, उन्हें बड़ी तिब्बती बस्तियों में मिला दिया जाना चाहिए। ये अल्पकालिक परियोजनाएं नहीं हैं जिन्हें एक या दो साल में पूरा किया जा सकता है। इसमें पांच-दस या अधिक वर्ष लग सकते हैं। हमें इन परियोजनाओं को एक सोची-समझी रणनीति के साथ अंजाम देना होगा अन्यथा हमें भविष्य में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इन मामलों पर मिलकर काम करेंगे।

हम जनसंख्या सर्वेक्षण की भी योजना बना रहे हैं। हम इसे अभी जनसांख्यिकीय मूल्यांकन नहीं कह रहे हैं क्योंकि जनसांख्यिकीय मूल्यांकन के लिए परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति, शिक्षा की स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि जैसी बहुत सारी जानकारियों की आवश्यकता होती है। हम केवल व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने की योजना बना रहे हैं। डेढ़ पृष्ठ की योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है और अन्य योजनाएं तैयार होने के क्रम में हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने में थोड़ी देरी हो चुकी है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इसे अगले साल तक स्थगित कर देना चाहिए। तब तक अधिकांश तिब्बती अपनी-अपनी बस्तियों में पहुंच जाएंगे। एक बार जब मुझे जनसंख्या सर्वेक्षण से सटीक आंकड़ा मिल जाता है, तो मेरे लिए इस आंकड़े के आधार पर परियोजनाएं बनाना आसान हो जाएगा। ऐसा करने से हमारी परियोजनाएं और नीतियां अधिक प्रभावी और कुशल होंगी। हालांकि, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इसलिए सर्वेक्षण पर भरोसा कर रहा हूं कि इसमें कोई बाधा या त्रुटि नहीं होगी। मेरा मानना है कि अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं लेकिन त्रुटियां मामूली होंगी।

तेनज़िन चेमे: इस समय तिब्बती समुदाय के सामने एक समस्या यह है कि तिब्बती संसद का सत्र आयोजित नहीं हो पा रहा है। इस कारण से तिब्बती संसद से बजटीय अनुमोदन प्राप्त करने जैसे प्रशासनिक कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि यह गतिरोध जारी रहा तो समस्या और विकट हो जाएगी। मामले पर आपकी क्या राय है?

सिक्योंग: जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मैं सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर रहा हूं। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम सब पहले तिब्बती हैं। मूल रूप से लोकतंत्र में हमें नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। हम नियमों को दरकिनार कर इसे लोकतंत्र कह कर आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बारे में सभी को सोचना होगा। यदि संसद पहले अपना एक सत्र आयोजित करती है, तो हम इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। यह तो हुई एक बात। दूसरी ओर, प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बाधा है। यदि संसद अपना सत्र आयोजित करती है और तदनुसार कलोनों (मंत्रियों) की नियुक्ति को मंजूरी देती है, तो कशाग की गतिविधियों

और क्षमताओं में निश्चित रुप से वृद्धि होगी। कलोन संबंधित विभागों की देखभाल करेंगे जबकि सिक्योंग अन्य महत्वपूर्ण कार्यों जैसे तिब्बती जनता और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के बीच संबंधों को मजबूत करने और चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने की दिशा में प्रयास करेंगे। निश्चय ही मुझे इन मामलों पर और अधिक समय देने के लिए और समय मिलेगा। बस इतना ही फर्क है। अन्यथा, कोई महत्वपूर्ण बाधा नहीं होगी। इसलिए मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कशाग की ओर से प्रशासनिक कार्यों में कोई लापरवाही नहीं होगी। कलोनों के न होने पर भी सचिवों के नेतृत्व में नौकरशाही का पूरा ढांचा है। प्रशासनिक कार्य कलोन और कर्मचारियों के प्रयासों का संगम है। सिक्योंग की जिम्मेदारी संभालने के बाद से मेरे तीन महीनों में स्टाफ बेहद सहयोगी रहा है। यहां तक कि युवा कर्मचारियों में भी बुनियादी वास्तविक ज्ञान और शिक्षा मजबूत है। सभी विभागों के निरीक्षण में मैंने प्रत्येक कर्मचारी से बात की और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और संबंधित वर्गों के कार्यों के बारे में जानकारी ली। यह निरीक्षण दौरा १६वें कशाग की मुख्य नीतियों, लक्ष्यों और उद्देश्यों से कर्मचारियों को परिचित कराने के उद्देश्य से किया गया था ताकि हम सभी एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर एक ही दिशा में आगे बढ़ सकें। यदि कर्मचारी और नेतृत्व एक-दूसरे के साथ तालमेल में नहीं चल रहे हैं तो हमारे सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करना वास्तव में कठिन होगा। इसलिए मैंने अब तक प्रशासन के पुनर्गठन में काफी समय बिताया। उदाहरण के लिए तीन विभागों में कोई अतिरिक्त सचिव नहीं थे। ये संकेत करते हैं कि नौकरशाही ढांचे के भीतर भी अंतराल हैं। नौकरशाही संरचना को पिरामिड की तरह माना जाता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। इसलिए, कार्य मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर नए कर्मचारी नियम बनाए जाएंगे और फेरबदल किए जाएंगे। यह प्रशासन के पुनर्गठन के लिए एक बार का फेरबदल होगा। उसके बाद सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा और हमेशा की तरह आगे बढ़ जाएगा। प्रशासन को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कर्मचारियों और कशाग- दोनों के प्रयासों में तालमेल होना चाहिए। ऐसे में कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि असली दिक्कतें अगले साल ३१मार्च के बाद सामने आएंगी। यदि तब तक संसदीय गतिरोध का समाधान नहीं होता है तो संभावना है कि सीटीए को बंद करना होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका असर न सिर्फ प्रशासन बल्कि स्कूलों और कई अन्य संस्थानों पर भी पड़ेगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हमें इसके बारे में सोचना होगा। अन्यथा जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, प्रशासनिक कार्यों के मामले में अगले वर्ष ३१ मार्च तक कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। बेशक, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा लेकिन केवल मामूली रुप से। हालांकि, एक बड़े दृष्टिकोण से प्रशासनिक कार्य सुचारु रुप से और कुशलता से चल रहा है। जनता को इसकी चिंता करने की जरुरत नहीं है।

तेनज़िन चेमे: आपने (सिक्योंग की जिम्मेदारी संभालने के बाद से) लद्दाख के लेह और झांगथांग क्षेत्रों से तिब्बती बस्तियों की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरु की। लद्दाख की पहली आधिकारिक यात्रा कैसी रही?

सिक्योंग: यह यात्रा बहुत ही फलदायी रही। मैंने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक वादा किया था कि अगर मैं सिक्योंग चुनाव जीतता हूं तो मैं लद्दाख से तिब्बती बस्तियों की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरु करुंगा। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि लद्दाख सुदूर क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है। अगर आपको झांगथांग इलाकों में जाना है तो आपको कम से कम २०० किलोमीटर का सफर तय करना होगा। अपनी यात्रा के दौरान मैंने पूरे खानाबदोश क्षेत्र का दौरा किया। लेह से न्योमा, न्योमा से कागशुंग, कागशुंग से घोयुल, घोयुल से हनले, हनले से मख्यू, मख्यू से सुमदोह और सुमदोह से राचुंगकारु तक चुमुर और साम्य की खानाबदोश बस्तियों तक की यात्रा की है। इसी तरह, मैंने चोगलमसर और लेह में सभी तिब्बती शिविरों और समुदायों का दौरा किया। मैंने लोगों के साथ अनौपचारिक बैठकें कीं, गरीबों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनीं। मैंने स्थानीय लद्दाखी समुदाय के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात की। मैंने बैठकों में भाग लिया और स्थानीय केबल टीवी के माध्यम से तिब्बती समुदाय को संबोधित किया। मैं जहां भी गया, लोगों से कहा कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि उनकी हर चिंता, सवाल और शिकायत नहीं सुन लेता। लोगों ने भी बिना किसी आशंका के अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। चूंकि मैं सब कुछ हल नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने साथ संबंधित कार्यालयों जैसे गृह विभाग से मिगमार भूटी, नारसांग और एसएआरडी से जुंगनी जैसे अधिकारियों को भी लाया ताकि संबंधित कर्मचारियों को मुद्दों की स्पष्ट और समग्र समझ हो सके। मेरे साथ तिब्बती सहकारी समिति, स्थानीय तिब्बती सभा, क्षेत्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, सीआरओ आदि के अधिकारी भी थे। वे ही इस काम को आगे बढ़ाएंगे। लोगों की चिंताओं और सुझावों के आधार पर मैं मुद्दों को हल करने के लिए एक ठोस योजना तैयार करुंगा, चाहे वह सिक्योंग के कार्यालय, गृह विभाग या मुख्य प्रतिनिधि कार्यालय से संबंधित मुद्दा हो। लद्दाख से रवाना होने से पहले मैंने यात्रा के बारे में करीब ४५ मिनट तक जनता को संबोधित भी किया। मेरे अपने अनुभव से, हमें मुद्दों को हल करने के लिए १०-१५ साल की लंबी अवधि की योजना तैयार करनी होगी क्योंकि लद्दाख में ज्यादातर चिंताएं जमीन से संबंधित थीं। कुछ मुद्दे खानाबदोश जीवन शैली की स्थिरता से संबंधित हैं। हालांकि, लद्दाख में सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की खोज के साथ-साथ अवसरों के रास्ते भी हैं।

आधिकारिक यात्रा के दौरान लद्दाख के लोगों ने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका मानना था कि परम पावन दलाई लामा के अधीन काम करने वाले प्रमुख व्यक्ति आए हैं। मैं अपने दिल में जानता हूं कि परम पावन दलाई लामा की कृपा और आशीर्वाद के कारण ही लद्दाख के लोगों ने मुझे इतना सम्मान और प्यार दिया है। ठिकसे रिनपोछे ने भी मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। जब मैं वहां गया तो मुझे लगा कि हम कुछ ही लोगों से मिलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने वहां एक बड़ा और भव्य समारोह आयोजित कर रखा था। मैं हिमालयन तिब्बत समर्थक समूह के सदस्यों और लद्दाख से भारतीय संसद के सम्मानित सदस्य जम्यांग त्सेरिंग नामग्याल से भी मिला। उन्होंने एक तिब्बती स्कूल से स्नातक किया है और वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं डीसी से मिला और सोवा रिग्पा इंस्टीट्यूट गया। लद्दाख भी पिछले दो साल से केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसलिए, मैं लद्दाख के मुख्य पार्षद और अन्य पार्षदों से मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे लद्दाख में लद्दाखियों और तिब्बतियों को एक ही मां के दो भाई मानते हैं और दोनों समुदायों को समान समर्थन और सुविधाएं प्रदान करते हैं। चूंकि तिब्बती भारतीय नागरिक नहीं हैं, इसलिए उन्हें सभी अवसर प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा, वे तिब्बतियों की मदद करने के लिए अपनी क्षमता से सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने लद्दाख में परम पावन दलाई लामा के समर्पित निवास शिव त्सेल फोडंग में एक लिफ्ट के निर्माण का भी वादा किया है। इस तथ्य की सराहना करते हुए कि तिब्बती और लद्दाखी समान संस्कृति, परंपराओं और सबसे महत्वपूर्ण परम पावन दलाई लामा के एकसमान भक्त हैं, वे यात्रा के दौरान मुझ पर बहुत विनीत और कृपालु रहे हैं। केवल एक व्यक्ति जिनसे मैं नहीं मिल सका, वह उपराज्यपाल थे। असल में २८ अगस्त को केंद्र सरकार का एक अधिकारी उनसे मिलने आया था। इसके अलावा, मैं लद्दाख में लगभग पूरे नेतृत्व से मिलने में सक्षम रहा। सौभाग्य से, हमारे प्रतिनिधिमंडल में से कोई भी बीमार नहीं पड़ा या हमें किसी अप्रिय घटना का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों ने हमें सलाह दी कि हमें अपने शरीर को ऊंचाई के अनुकूल होने देने के लिए आगमन पर कुछ आराम करने की आवश्यकता है। हालांकि, हमने बिना आराम किए अपनी यात्रा शुरु कर दी। हमारा दिन लगभग हर दिन सुबह ८ बजे शुरु होता था और लगभग १० बजे रात को समाप्त होता था। संक्षेप

में, मुझे खुशी है कि मैं जनता से मिल पाया और जनता मुझसे मिलकर खुश लग रही थी। मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं लोगों को धोखा नहीं देता या झूठे वादे नहीं करता। मैंने उन्हें बताया कि जो कुछ मुझे लगा वह सच और सटीक था। जनता की मदद करने और उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए मुझे सबसे पहले उनकी स्थिति, उनकी जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं को समझना होगा। इन्हें समझे बिना हम चाहकर भी कुछ कारगर नहीं कर सकते थे। इसलिए, यह यात्रा वास्तव में सहायक और ज्ञानवर्धक रही। मैं अन्य तिब्बती बस्तियों के साथ भी ऐसा करने की योजना बना रहा हूं ताकि हमारी परियोजनाएं उचित रणनीति के आधार पर सुविचारित और अच्छी तरह से सुनियोजित हों। दानदाताओं से हमें जो पैसे मिल रहे हैं, वह हमारे देशों के लोगों की मेहनत की कमाई से वसूला गया कर का पैसा है। हम इसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते, हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। इसे यूं ही बर्बाद करना बौद्ध दृष्टिकोण से भी एक पाप है। जब मैंने अपनी योजनाओं और उद्देश्यों के बारे में बताया, तो जनता ने वास्तव में इसकी सराहना की। यह मेरा गहरा विश्वास है कि सार्वजनिक रूप से निर्वाचित सिक्योंग के रूप में जनता के प्रति मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस रवैये के साथ मैं लोगों से मिला, उनसे बातें कीं और उनके हर एक सवाल, शिकायत और चिंताओं को सुना।

• सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू से शिष्टाचार मुलाकात की

tibet.net, १३ सितंबर, २०२१

धर्मशाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने आज १३ सितंबर की सुबह भारत के माननीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की।

सिक्योंग के साथ नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा ब्यूरो के प्रतिनिधि न्गोडुप डोंगचुंग भी थे।

बाद में दोपहर में सिक्योंग ने शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती लामचोंघोई स्वीटी चांगसन और सीटीएसए के संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की और छह केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) के हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर चर्चा की, जिन्हें अभी शिक्षा विभाग के संभूता तिब्बती स्कूल सोसाइटी (एसटीएसएस) स्कूलों में हस्तांतरित किया जाना है।

दिल्ली की अपनी निर्धारित यात्रा से पहले सिक्योंग शिक्षा सचिव जिग्मे नामग्याल और संभूता तिब्बती स्कूल सोसाइटी (एसटीएसएस) के निदेशक त्सेरिंग धोंडुप के साथ पूरे भारत में छह बचे सीटीएसए स्कूलों के सप्ताह भर के मूल्यांकन दौरे में लगे हुए थे। ये छह स्कूल हैं- सीएसटी मसूरी, सीएसटी शिमला, सीएसटी डलहौजी, सीएसटी कलिम्पोंग, सीएसटी दार्जिलिंग और सीएसटी हरबर्टपुर। उन्होंने इन स्कूलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और इन स्कूलों के संबंधित कर्मचारियों के साथ उनके दृष्टिकोण और सुझावों को समझने के लिए बातचीत की, जिसके आधार पर उन्होंने दिल्ली में अपनी बैठक के दौरान चर्चा की।

• संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने तिब्बती बौद्ध विद्वान गो शेरब ग्यात्सो और रिनचेन त्सुल्ट्रिम की स्थिति के बारे में चीन से सवाल किया

tibet.net, १६ सितंबर, २०२१ जिनेवा।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के एक समूह ने संयुक्त रूप से लापता तिब्बती बौद्ध विद्वान गो शेरब ग्यात्सो के गायब किए जाने और रिनचेन त्सुल्ट्रिम को मनमाने ढंग

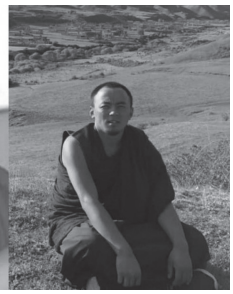

से हिरासत में लिए जाने के मामलों के बारे में चीन से पूछताछ की है। दोनों तिब्बती भिक्षु पूर्वी तिब्बत के अमदो के न्गाबा के रहनेवाले हैं।

गो शेरब ग्यात्सो के जबरन गायब होने और रिनचेन त्सुल्ट्रिम को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इनफोर्स्ड ओर इनवॉलुंटरी डिसएपियरेंसेंज, वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिटररी डिटेंशन, स्पेशल रिपोर्टियर ऑन माइनोरिटी इशुज और स्पेशल रिपोर्टियर ऑन फ्रीडम ऑफ रिलिजन ओर बिलीफ जैसे संगठनों ने संयुक्त रूप से चीन को प्रेषित संचार में गो शेरब ग्यात्सो के ठिकाने के बारे में 'तत्काल' जानकारी प्रदान करने और रिनचेन त्सुल्ट्रिम की गिरफ्तारी, हिरासत और सजा के लिए कानूनी आधार बताने का आह्वान किया है।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने आगे कहा है कि 'ये हिरासत अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं', बल्कि चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बतियों को मनमाने ढंग से और अनौपचारिक रूप से हिरासत में लेने, बंद कमरे में सुनवाई करने और अज्ञात आरोपों में अज्ञात तरीके से फैसला देने के एक व्यवस्थित पैटर्न को दर्शाते हैं। विशेषज्ञों ने यह भी चिंता व्यक्त की कि चीन द्वारा व्यक्ति को धर्म और जातीयता के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है।

ज्ञात हो कि तिब्बती बौद्ध विद्वान गो शेरब ग्यात्सो को २६ अक्तूबर २०२० को सिचुआन प्रांत के चेंगदू में गिरफ्तार किया गया था, तब से उनकी सेहत और ठिकाने के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। गो शेरब ग्यात्सो ने तिब्बती दर्शन और संस्कृति और मठवासी शिक्षा प्रणाली पर कई किताबें लिखी हैं। गो शेरब ग्यात्सो को पहले चीनी अधिकारियों ने १९९८ और २००८ में भी हिरासत में लिया था।

२७ जुलाई २०१९ को न्गाबा पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के चीनी अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए जाने के बाद से न्गाबा में नंगशिंग मठ के भिक्षु रिनचेन त्सुल्ट्रिम को मनमाने तरीके से हिरासत में रखा गया है। इसके बाद एक बार ही उनके बारे में खबर २३ मार्च २०२१ को सामने आई कि उन्हें साढ़े चार की सजा सुनाई गई है। उसके खिलाफ आरोपों, सुनवाई की तारीख और मुकदमा वाली अदालत के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

भारत ने स्वतंत्रता हासिल की और भारतीयों को आजादी की स्वर्णिम रोशनी में जगमगाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के

कई देशों ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की। जब दुनिया के बाकी देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे, दुर्भाग्य से इसी दौर में तिब्बत पर चीन द्वारा आक्रमण किया गया। उन्होंने आग्रह किया कि भविष्य में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मैं तिब्बत के अंदर और बाहर रहनेवाले तिब्बतियों से पूरे दिल से खुद को समर्पित होने का आग्रह करता हूं।'

सीसीपी द्वारा तथाकथित 'तिब्बत मुक्ति दिवस' की ७०वीं वर्षगांठ के हालिया उत्सव के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में सिक्योंग ने कहा कि जिसे चीन 'मुक्ति दिवस' के रुप में मनाता है, वह हम तिब्बतियों के लिए 'कब्जे और उत्पीड़न' की वर्षगांठ है।'

स्टेट काउंसिल ने हाल ही में चीन के अंदर मानवाधिकार की स्थिति और विशेष रुप से अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विकास की स्थिति पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। यह रिपोर्ट केवल सीसीपी के तहत हुई प्रगति को दिखाती है। जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों में लोगों द्वारा प्राप्त किए गए अहस्तांतरणीय मौलिक अधिकार, जिनकी सरकारों को रक्षा करनी चाहिए, को इस श्वेत पत्र में बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। तिब्बत और चीनी कब्जे वाले अन्य क्षेत्रों में मानवाधिकारों का उल्लंघन अभी भी जारी है। तिब्बत की मुक्ति के सीसीपी के दावों से सवाल उठता है- तिब्बत को किससे या किस तरह से मुक्त कराया गया था? सिक्योंग ने कहा कि मुक्ति की बजाय तिब्बती पिछले ७० वर्षों से तड़प रहे हैं और यह उत्सव का कोई औचित्य नहीं है।

• जेल से रिहा होने के बाद आठ साल तक बीमार रहने के बाद तिब्बती लेखक का निधन

rfa.org, २०२१-०९-१६

तिब्बत में चीनी सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले लेखों को प्रकाशित करने के लिए रा त्सेरिंग धोंडुप को २०१० में तीन साल के लिए जेल में डाल दिया गया था।

तिब्बती सूत्रों का कहना है कि तिब्बत में चीनी सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए तीन साल के लिए जेल में बंद एक तिब्बती लेखक की रिहाई के बाद आठ साल तक बीमार रहने के बाद सिचुआन की राजधानी चेंगदू में इस सप्ताह मृत्यु हो गई।

रात्सेरिंग धोंडुप, जिन्होंने शिंग्लो मारपो नाम से लिखा था, सिचुआन के न्गाबा (चीनी, आबा) तिब्बती स्वायत्त प्रान्त में ख्युंगचु काउंटी में रोंगथा मठ में एक भिक्षु थे, जिनकी मृत्यु ३४ वर्ष की आयु में हो गई।

अब भारत में रह रहे धोंडुप के दोस्त और पूर्व सहयोगी गेंडुन त्सेरिंग ने आरएफए की तिब्बती सेवा को बताया कि धोंडुप को एक पत्रिका प्रकाशित करने के लिए फरवरी २०१० में गिरफ्तार किया गया था। इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री में चीनी कम्युनिस्ट सरकार की आलोचना की गई थी।

गेंडुन ने कहा, 'उन्हें पहले बरखाम में हिरासत में लिया गया था और बाद में उसे तीन साल की सजा पूरी करने के लिए मियांयांग जेल भेज दिया गया था। इसके बाद उन्हें २०१३ में रिहा कर दिया गया था। लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और बाद में उन्होंने लीवर की बीमारी के कारण दम तोड़ दिया।'

निर्वासन में रह रहे धोंडुप के एक अन्य मित्र ने बताया कि धोंडुप द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका ने २००८ में चीनी शासन का विरोध करने के साथ तिब्बत में स्थितियों का वर्णन किया था, जिसके कारण चीनी सुरक्षा बलों के हाथों सैकड़ों गिरफ्तारियां और मौतें हुईं।

उन्होंने कहा, 'रा त्सेरिंग धोंडुप के एक और दोस्त और मैंने खुद उस पत्रिका के लिए साथ काम किया। हालाँकि, यह केवल एक ही बार प्रकाशित हुआ था।'

भारत के धर्मशाला स्थित तिब्बतन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के शोधकर्ता तेनजिन दावा ने कहा, 'कठोर व्यवहार और जेल में चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण धोंडुप की रिहाई के बाद आठ वर्षों के दौरान उनकी हालत गंभीर रुप से खराब हो गई थी।'

सूत्रों का कहना है कि बीमार और खराब स्वास्थ्य वाले तिब्बती राजनीतिक कैदियों को कभी-कभी उनकी सजा पूरी होने से पहले ही गंभीर स्थिति में रिहा कर दिया जाता है। पिछले वर्ष के दौरान ऐसे कम से कम सात कैदियों की मृत्यु की सूचना दी गई थी, जिनकी हिरासत में यातना के तहत लगी चोटों से या तो जेल में या रिहाई के बाद मौत हो गई।

दावा ने बताया कि यह अपने अपराधों के लिए जिम्मेदारी से बचने का चीनी सरकार का तरीका है।

पूर्व में एक स्वतंत्र राष्ट्र रहे तिब्बत पर ७० साल पहले चीन द्वारा आक्रमण किया गया था और उसे बलपूर्वक चीन में शामिल किया गया था।

इस दौरान चीनी अधिकारियों ने इस क्षेत्र पर अपना कड़ा नियंत्रण बनाए रखा। तिब्बतियों की राजनीतिक गतिविधियों और सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित किया गया और तिब्बतियों को उत्पीड़न, यातना, कारावास दी गई और उनकी कानूनी तरीका अपनाए बिना ही हत्या तक कर दी गईं।

आरएफए की तिब्बती सेवा के लिए उग्येन तेनज़िन और ल्हुबूम द्वारा तैयार रिपोर्ट। तेनज़िन डिकी द्वारा अनुदित। रिचर्ड फिनी द्वारा अंग्रेजी में लिखित।

किंघई भूकंप के बाद पुनर्निर्माण में 'चीनी-शैली' के घरों से तिब्बतियों को डर लगता है

•भूकंप से बचे कुछ लोगों का कहना है कि नवनिर्मित संरचनाएं पारंपरिक तिब्बती स्थापत्य शैली को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।

rfa.org, २०२१- ०९-२३

इस साल की शुरुआत में उत्तर-पश्चिम चीन के किंघई में एक तिब्बती आबादी वाले काउंटी में भूकंप के बाद चीनी अधिकारियों द्वारा पुनर्निर्माण किया जा रहा है। लेकिन भूकंप से बचे लोगों का कहना है कि उन्हें डर है कि घरों और मठों को चीनी शैली में फिर से बनाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इससे उनका पारंपरिक तिब्बती स्वरुप नष्ट हो जाएगा।

स्थानीय सूत्रों ने आरएफए को पहले की रिपोर्टों में बताया कि २२ मई को किंघई के माटो (चीनी, मडुओ) काउंटी में ७.३ तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कम से कम २० लोगों की मौत हो गई थी और ३०० से अधिक घायल हो गए थे।

चीनी अधिकारियों ने क्षेत्र से सूचना प्रवाह को अवरुद्ध कर हताहतों के आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि को रोकने के लिए तेजी से सारे उपाय किए।

इस क्षेत्र में रहने वाले एक तिब्बती ने इस सप्ताह आरएफए की तिब्बती सेवा को बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने जुलाई में प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए काम शुरू किया और पुराने घरों और मठों को ध्वस्त कर दिया।

आरएफए के सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'वे न केवल भूकंप से प्रभावित हुए ढांचे को बल्कि उन संरचनाओं को भी गिरा रहे हैं जो प्रभावित नहीं हुए थे।'

'और आम लोगों या भिक्षुओं की इच्छाओं को जाने या उनसे परामर्श किए बिना वे अपने घरों और क्वार्टरों को ध्वस्त कर रहे हैं और वहां पर स्टील के घरों का निर्माण कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'अब यह बहुत बड़ी चिंता की बात है कि सरकार जल्द ही पूरे क्षेत्र में ऐसे

घरों को फिर से बना सकती है जो केवल चीनी स्थापत्य के अनुकूल होंगी।'

सूत्र ने कहा, 'भले ही मई में भूकंप से गंभीर क्षति हुई हो, फिर भी सब कुछ नष्ट करने का कोई कारण नहीं है।' चीनी अधिकारी वादा कर रहे हैं कि नई संरचनाएं भविष्य में भूकंप का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगी और कि अन्य घर भी अंततः बनाए जाएंगे।

सूत्र ने कहा, 'हालांकि, यह सभी नए निर्माण केवल सरकार के एजेंडे के अनुसार हो रहे हैं। उधर, तिब्बती चिंतित हैं कि इन नवनिर्मित भवनों में कोई तिब्बती शैली नहीं बचेगी।'

चीनी सरकारी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, माटो के तिब्बती निवासियों को २२ मई को आए भूकंप से नुकसान से संबंधित रिपोर्ट पोस्ट करने से रोक दिया गया था। यहां का भूकंप दक्षिण-पश्चिमी चीन के युन्नान प्रांत में ६.४ तीव्रता के भूकंप के बाद उसी दिन आया था, जिसमें कम से कम तीन लोग मारे गए थे और ३२ लोग घायल हो गए थे।

१४ अप्रैल, २०१० को किंघई के युशुल (युशू) तिब्बती स्वायत्त प्रान्त में आए भूकंप ने क्यूगुडो शहर को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया, हजारों निवासियों को बेघर कर दिया और आधिकारिक गणना के अनुसार लगभग ३००० लोगों की मौत हो गई थी।

चीनी सुरक्षा बल बाद में तिब्बती परिवारों को उनके लिए बनाए गए नए घरों से उन्हें तब बेदखल करने लगे जब निवासियों ने कहा कि वे अतिरिक्त निर्माण की लागत राशि सरकार को वापस नहीं कर सकते।

सूत्रों ने कहा कि जनवरी २०१५ में क्येगुडो में निवासियों से अधिकारियों द्वारा पैसों की मांग की गई और सैकड़ों पुलिसकर्मियों को सरकार द्वारा निर्मित आवास परियोजनाओं में तैनात कर दिया गया।

तिब्बत और चीन के तिब्बती क्षेत्रों में रहने वाले तिब्बती अक्सर राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक भेदभाव के साथ-साथ मानवाधिकारों के हनन की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि उन्हें डर है कि बीजिंग ६० लाख तिब्बतियों को चीनी हान मूल में मिला देने की नीतियों को तेजी से लागू कर रहा है।

आरएफए की तिब्बती सेवा के लिए संग्याल कुंचोक की रिपोर्ट। तेनज़िन डिकी द्वारा अनूदित। रिचर्ड फिनी द्वारा अंग्रेजी में लिखित।

• भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय की नई संशोधित हिंदी वेबसाइट लाँच

Tibet.net, ०४ सितंबर, २०२१

०४ सितंबर २०२१, नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित भारत-तिब्बत समन्वय

कार्यालय (आईटीसीओ) को अपनी नई संशोधित हिंदी वेबसाइट यानीwww.indiatibet.netके शुभारंभ की घोषणा किए।

पुन: डिज़ाइन की गई वेबसाइट में सुविधाओं, विशिष्टताओं और पहुंच के मामले में काफी सुधार किया गया है। इसे अधिक विस्तृत और विशिष्टताओं के साथ डिजाइन किया गया है जो अधिक से अधिक लक्षित समूहों तक पहुंचने में अभूतपूर्व होगा। भारत में इस वेबसाइट पर तिब्बत, परम पावन दलाई लामा, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बत सहायता समूहों से संबंधित सूचनाएं और समाचार हिंदी में प्रसारित होंगी। इस पर भारतीय तिब्बत समर्थक समूहों द्वारा समय-समय पर की जाने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों को भी पोस्ट किया जाएगा।

पुन: डिज़ाइन की गई वेबसाइट त्वरित प्रदर्शन और व्यापक पहुंच के साथ तेजी से प्रतिक्रिया भी देती है। यहां सामग्री आकर्षक और स्पष्ट रूप से दिखती है और फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया लिंक आइकन साझा करने के उद्देश्य से शामिल किए गए हैं और यहां से प्रिंट भी ले सकते हैं। पाठकों के लिए आईटीसीओ की मासिक हिंदी पत्रिका 'तिब्बत देश' और अन्य प्रकाशनों की सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अद्यतन वेबसाइट में यूजर इंटरफेस और डाउनलोड करने योग्य प्रकाशनों में सुधार किया गया है।

पुन: डिज़ाइन की गई वेबसाइट पर व्यापक स्तर पर दर्शकों के लिए तिब्बत टीवी का साप्ताहिक हिंदी समाचार 'तिब्बत इस सप्ताह' शामिल किया गया है। वेबसाइट पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का वर्चुअल दौरा भी शामिल किया गया है।

वेबसाइट को सीधे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइटों यानी- तिब्बती (www.bod.asia), अंग्रेजी (www.tibet.net) और चीनी (www.xizang-zhiye.org) पर सबसे ऊपर दाहिने कोने में भाषा सूची में जाकर वहां हिन्दी विकल्प पर क्लिक करके हिन्दी में पढ़ा जा सकता है।

भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय वेबसाइट को संभव बनाने में सीटीए के नेतृत्व में डीआईआईआर के तिब्बती कंप्यूटर संसाधन केंद्र (टीसीआरसी) की ओर से दिए गए मदद और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देना और उनकी सराहना करना चाहता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय की वेबसाइटhttps://www.indiatibet.netपर जाएं।

• आईटीसीओ और तिब्बत समर्थक समूहों के प्रतिनिधिमंडल ने तवांग में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से शिष्टाचार भेंट की

tibet.net, २३ सितंबर, २०२१

बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश। ३० जुलाई २०२१ को असम के गुवाहाटी में आयोजित तिब्बत समर्थक समूहों की प्रारंभिक बैठक में तय किए गए एजेंडे के अनुरुप, भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय- दिल्ली के समन्वयक श्री जिग्मे त्सुल्ट्रिम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू से सोमवार, २० सितंबर, २०२१ को उनके तवांग स्थित आवास पर भेंट की।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख श्री जिग्मे त्सुल्ट्रिम ने सीएम खांडू को सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग की अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर की आगामी यात्रा के बारे में जानकारी दी। इस पर सीएम खांडू ने यात्रा और आगे के कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक सभी सहायता देने का आश्वासन दिया है।

अगले दिन २१ सितंबर की सुबह प्रतिनिधिमंडल ने तवांग मठ का दौरा किया और

मठ के वरिष्ठ प्रशासकों से मुलाकात की। प्रशासकों को सिक्योंग की आगामी यात्रा के बारे में भी जानकारी दी गई।
प्रतिनिधिमंडल में भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय- दिल्ली के समन्वयक श्री जिग्मे त्सुल्ट्रिम; कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया के क्षेत्रीय संयोजक श्री सौम्यदीप दत्ता; भारत तिब्बत सहयोग मंच - अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष श्री वांगडी दोरजी खिरमे; भारत तिब्बत सहयोग मंच- तवांग जिला के अध्यक्ष श्री लुंडुप चोसांग; तेनजिंगंग के तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी श्री यांगडुप और तिब्बती सेटलमेंट कार्यालय- बोमडिला के कार्यालय सचिव सह समन्वयक श्री चिसा त्सेल्हा शामिल थे।

•आईटीसीओ समन्वयक और टीएसओ शिलांग ने मेघालय के मुख्य सचिव से मुलाकात की

tibet.net, २४ सितंबर, २०२१

२३ सितंबर, २०२१, शिलांग। तवांग में अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय के समन्वयक श्री जिग्मे त्सुल्ट्रिम और तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी श्री पेमा धोंडुप ने मेघालय सरकार के मुख्य सचिव श्री एम.एस. राव से गुरुवार, २३ सितंबर, २०२१ को मुख्य सचिवालय भवन, शिलांग में मुलाकात की।
प्रारंभ में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को पवित्र खटक (तिब्बती सफेद दुपट्टा) के साथ एक ताशी टैगे (आठ शुभ संकेत) और एक पुस्तक भेंट की। श्री जिग्मे त्सुल्ट्रिम ने मुख्य सचिव को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और निर्वासन में तिब्बतियों के कल्याण की देखभाल करने और तिब्बती हित के लिए काम करने में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने परम पावन के नेतृत्व में तिब्बतियों के लिए पिछले छह दशकों से भारत सरकार और भारत के लोगों की उदारता के बारे में भी उनके साथ बातें कीं।

श्री जिग्मे त्सुल्ट्रिम ने मुख्य सचिव को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष माननीय सिक्योंग श्री पेनपा त्सेरिंग की मेघालय सहित पूर्वोत्तर की आगामी यात्रा के बारे में भी जानकारी दी। मुख्य सचिव ने एक-एक शब्द को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार माननीय सिक्योंग की शिलांग यात्रा के दौरान हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।

प्रतिनिधिमंडल ने अपनी ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त किया और मुख्य सचिव को उनके व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्हें समय देने के लिए धन्यवाद दिया।

• संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने ४८वें यूएनएचआरसी सत्र में चीन से तिब्बत में मानवाधिकारों का सम्मान करने का आह्वान किया

tibet.net, २८ सितंबर, २०२१

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के चल रहे ४८वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के एक समूह ने चीन से तिब्बत में मानवाधिकारों का सम्मान करने का आह्वान किया।
२६ सदस्य देशों की ओर से डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विटजरलैंड, अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की और चीन से तिब्बत, झिंझियांग और हांगकांग में मानवाधिकारों का सम्मान करने का आह्वान किया है।

अमेरिका ने मानवाधिकार की स्थिति पर एक बयान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का ध्यान आकृष्ट करते हुए चीन द्वारा आर्थिक शोषण, प्रणालीगत नस्लीय संहार और सांस्कृतिक विरासत के विनाश सहित मानवाधिकारों के हनन की कड़ी निंदा की। तिब्बत में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं पर चीन के गंभीर प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका चिंतित रहता है।
फ्रांस ने २६ सदस्य देशों की ओर से यूरोपीय संघ का बयान पढ़ा। यूरोपीय संघ ने चीन से मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए कहा, जिसमें अल्पसंख्यकों विशेष रूप से तिब्बत, झिंझियांग और आंतरिक मंगोलिया से संबंधित व्यक्तियों के अधिकार शामिल हैं।

डेनमार्क ने तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्टों के बारे में अपनी 'गहरी चिंता' व्यक्त की। प्रतिनिधि ने उच्चायुक्त और अन्य स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की वहां सार्थक पहुंच प्रदान करने के लिए चीन से आह्वान को दोहराया। इसी चिंता को व्यक्त करते हुए जर्मन प्रतिनिधि ने कहा कि जर्मनी तिब्बत में चीन द्वारा व्यवस्थित मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में 'गंभीर रूप से चिंतित' है।
नीदरलैंड किंगडम ने चीन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताओं को प्रकट किया, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और तिब्बत में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध शामिल है। स्विट्जरलैंड ने चीन द्वारा अल्पसंख्यकों को मनमाने ढंग से हिरासत में रखने की निंदा की और चीन से तिब्बती लोगों के अधिकारों का सम्मान करने का आह्वान किया। इसी तरह, स्वीडन के प्रतिनिधि ने तिब्बत सहित अल्पसंख्यकों, मानवाधिकार रक्षकों और मीडिया कर्मियों को निशाना बनाकर चीन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की।
इंग्लैंड, फ़िनलैंड और नॉर्वे के प्रतिनिधियों ने भी चीन द्वारा मानवाधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है।

• यूरोपीय संघ-चीन रणनीति पर यूरोपीय संसद की रिपोर्ट में तिब्बतियों के उत्पीड़न को लेकर चिंता

savetibet.org , १६ सितंबर, २०२१

ब्रसेल्स। यूरोपीय संसद ने आज १६ सितंबर को नई यूरोपीय संघ-चीन रणनीति पर एक रिपोर्ट को स्वीकार किया जिसमें तिब्बत में जबरन श्रम कार्यक्रमों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट में राजनयिकों और पत्रकारों के लिए तिब्बती क्षेत्रों में स्वतंत्र आवागमन की अनुमति दिए जाने का आह्वान किया गया है और तिब्बती समुदाय में धार्मिक नेताओं के चयन पर चीन द्वारा सुनियोजित किए जा रहे नियंत्रण की आलोचना की गई है।
यूरोपीय संसद के सदस्य हिल्डे वॉटमैन (बेल्जियम, रिन्यू यूरोप ग्रुप) द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट में छह स्तंभों पर आधारित एक रणनीति का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें से दूसरा 'सार्वभौमिक मूल्यों, अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और मानवाधिकारों पर बेहतर जुड़ाव'

पर केंद्रित है।

यूरोपीय संसद के सदस्यों का कहना है कि रिपोर्ट के इस भाग में 'तिब्बत में बलपूर्वक श्रम कार्यक्रमों की रिपोर्ट' से बेहद चिंतित हैं और चीन से झिंझियांग, तिब्बत और आंतरिक मंगोलिया में नस्लीय समूहों के अधिकारों सहित मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का आह्वान करते हैं।

रिपोर्ट की सबसे अहम बात यह है कि इसमें यूरोपीय आयोग से चीनी अधिकारियों को 'एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलिजियस क्लेर्जी (ऑर्डर नं. १५)' के लिए चीन के उपायों पर उसकी चिंताओं से अवगत कराने का आह्वान किया गया है, जो धार्मिक गुरुओं के चयन में चीन सरकार के नियंत्रण को और बढ़ाता है।

हाल के वर्षों में, चीनी सरकार बौद्ध धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप करते हुए और तिब्बती बौद्ध समुदाय के बिना किसी सरकारी दखलंदाजी के अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया का पालन करने के मौलिक अधिकार को दरकिनार करते हुए अगले दलाई लामा के चयन में अपने अधिकार के दावे को अधिक से अधिक वैध बनाने के लिए ऐसे कानूनों और नियमों का उपयोग कर रही है।

इंटरनेशनल कंपेन फॉर तिब्बत (आईसीटी) के यूरोपीय संघ के नीति निदेशक विंसेंट मेटेन ने कहा, 'आईसीटी इस व्यापक रिपोर्ट का स्वागत करता है, जो व्यापक परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय संघ-चीन संबंधों के बारे में विमर्श करता है। हम इस रिपोर्ट में विशेष रुप से मानवाधिकारों पर यूरोपीय संसद के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई गंभीर चिंताओं और विशेष कर तिब्बतियों पर लगाए गए जबरन श्रम कार्यक्रमों के बारे में रिपोर्टों के साथ-साथ धार्मिक नेताओं के चयन में चीन के जनवादी गणराज्य के हस्तक्षेप पर भी इसमें व्यक्त की गई गंभीर चिंताओं का स्वागत करते हैं। यह चीन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में हस्तक्षेप करने की योजना बना रहा है।

प्रतिबंध और संवाद

यूरोपीय संसद के सदस्यगण यह भी रेखांकित करते हैं कि यूरोपीय संघ-चीन व्यापक निवेश समझौते के लिए विचार और अनुसमर्थन प्रक्रिया तब तक दोबारा शुरु नहीं हो सकती जब तक कि यूरोपीय संसद के सदस्यों और यूरोपीय संघ के संस्थानों (मानव अधिकारों पर उप-समिति और राजनीतिक और सुरक्षा समिति सहित) के खिलाफ चीन अपना प्रतिबंध हटा नहीं लेता है।

चीनी प्रतिबंध को यूरोपीय संसद के सदस्य गैरकानूनी और अवैधानिक मानते हैं। इनका मानना है कि चीन ने ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ द्वारा चीन में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ अपने काम और कार्रवाई को जारी रखने से रोकने के प्रयास के तौर पर लगाए हैं। यूरोपीय संघ ने अपनी कार्रवाई के तहत इसी साल मार्च में चार चीनी नागरिकों के खिलाफ अपने 'नए वैश्विक मानवाधिकार प्रतिबंध कानून' को लागू किया था। यह कानून उस एक चीनी संस्थान के खिलाफ भी लागू किया गया था जो झिंझियांग- उग्यूर स्वायत्त क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था।

यूरोपीय संघ और चीन के बीच राजनीतिक संबंध तब से खराब चल रहे हैं। इसी का कारण है कि बीजिंग अगले यूरोपीय संघ-चीन शिखर सम्मेलन और वार्षिक यूरोपीय संघ-चीन मानवाधिकार वार्ता के लिए नई तारीखों पर सहमत होने में आनाकानी कर रहा है, जो पिछली बार दो वर्ष पहले अप्रैल २०१९ में ब्रसेल्स में हुआ था।

आईसीटी सहित कई गैर सरकारी संगठन इस वार्ता के बारे में आलोचनात्मक रहे हैं, जो अब तक चीन में मानवाधिकार की स्थिति में सुधार करने में विफल रहा है और वर्षों से चीनी पक्ष द्वारा धीरे-धीरे अप्रासंगिक बना दिया गया है (जिसमें संवाद को साल में दो बार आयोजित करने के बजाय साल में एक बार ही करना और हिरासत की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और राजनीतिक बंदियों की स्थिति के बारे में जानकारी देने में चीन की आपत्ति या इनकार में झलकता है)।

आईसीटी और अन्य गैर सरकारी संगठनों ने चीनी डायस्पोरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों और सांसदों सहित एक पूरक छाया संवाद शुरु करने का आह्वान किया है ताकि चीनी प्रणाली की बेहतर समझ बनाई जा सके और चीन में मानवाधिकारों की प्रगति को प्रभावित करने और यूरोपीय संसद की वर्तमान रणनीति के तह बेहतर रणनीति तैयार की जा सके।

ओलंपिक

अंतिम लेकिन जोरदार बात यह है कि, यूरोपीय संसद के सदस्यों ने अपनी उस मांग को दोहराया, जो पहले से ही इस साल की शुरुआत में अपनाए गए एक प्रस्ताव में व्यक्त किया गया था। यह प्रस्ताव कहता है कि यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नेताओं को २०२२ के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के निमंत्रण को अस्वीकार कर देना चाहिए, अगर चीन और हांगकांग में मानवाधिकार की स्थिति में सुधार नहीं होता है और खेलों से पहले कोई उच्चस्तरीय यूरोपीय संघ-चीन मानवाधिकार वार्ता/सम्मेलन का एक ठोस परिणाम नहीं निकल जाता है।

• लेबर पार्टी के वार्षिक सम्मेलन २०२१ में लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय ने भाग लिया

tibet.net, २९ सितंबर, २०२१

लंदन। लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय ने २५-२८ सितंबर २०२१ के बीच इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित ब्राइटन में आयोजित लेबर पार्टी के वार्षिक सम्मेलन-२०२१ में १५० पंजीकृत प्रदर्शनियों के बीच अपनी ओर से एक प्रदर्शनी लगाई।

ब्रिटेन के राजनीतिक दल का सम्मेलन हर साल शरद ऋतु में कुछ दिनों के लिए देश की नीतियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने और बहस करने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिसमें नेतृत्व द्वारा बीज भाषण दिया जाता है, सदस्यों के साथ संबंधों को मजबूत किया जाता है और पार्टी के लिए समर्थन को मजबूत किया जाता है। पार्टी सम्मेलन का उद्देश्य पार्टी से जुड़े और पार्टी में रुचि रखने वाले लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन प्राप्त करना भी होता है, जिसमें पार्टी के सदस्य, राजनेता, कार्यकर्ता, पत्रकार, दानदाता, व्यवसायी आदि शामिल हैं।

लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय का ब्रिटेन के राजनीतिक दल के सम्मेलन में प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य पार्टी के नेताओं, सदस्यों और सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों को तिब्बत मुद्दे की जानकारी देना और उनके साथ संपर्क करने का अवसर लेना था।

कार्यालय इस अवसर पर शामिल होकर खुद को सम्मानित महसूस करता है और खुश है कि ब्रिटेन की संसद में तिब्बत के लिए सर्वदलीय संसदीय समूह के माननीय सांसद केरी मैकार्थी और माननीय नवेंदु मिश्रा समेत लेबर पार्टी के माननीय सांसदों ने तिब्बत कार्यालय के प्रदर्शनी स्टाल का दौरा किया और कार्यालय के प्रतिनिधि श्री सोनम त्सेरिंग फ्रासी से मुलाकात कर तिब्बत और तिब्बतियों के प्रति अपने समर्थन

और एकजुटता को निरंतर जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई।
यह कार्यालय पश्चिमी इंग्लैंड के मेयर डैन नॉरिस, पार्टी के सदस्यों, रहीमा महमूत सहित मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और ब्रिटेन में विश्व उग्यूर कांग्रेस के निदेशक द्वारा तिब्बत के लिए अपना समर्थन जताने पर भी प्रसन्न है। इन चार दिनों के आयोजनों में हम जिन लोगों से भी मिले, उन्होंने तिब्बत मुद्दे में बड़ी रुचि दिखाई और वहां की जलवायु और मानवाधिकार की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित दिखे।
कार्यालय को व्यक्तिगत संगठनों और व्यवसायों द्वारा आयोजित राजनीतिक संचार, मानवाधिकार, चीन और नैतिक निवेश, नेट ज़ीरो जलवायु के भविष्य सहित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला।
तिब्बत कार्यालय की सचिव सुश्री त्सेरिंग त्सोमो ने एशिया और प्रशांत के छाया मंत्री सांसद स्टीफन किन्नॉक से तिब्बत में बिगड़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चीन पर दबाव बनाने और तिब्बती पठार पर जलवायु संकट को वैश्विक जलवायु वार्ता में शामिल करने में उनसे समर्थन के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तिब्बत को उनका पूरा समर्थन है और वह टीएआर के पूर्व पार्टी सचिव, चीनी अधिकारी चेन क्वांगुओ को यूके सरकार द्वारा प्रतिबंध सूची में डालने और उन्हें यहां आने से प्रतिबंधित करने का पुरजोर समर्थन करते हैं।
तिब्बत के कार्यालय में ब्रिटेन में तिब्बती विश्वविद्यालय के तीन छात्र शामिल हैं। कार्यालय ने तेनज़िन रब्गा ताशी, मिफ़ाम समतेन और लोबसांग फुंतसोक को तिब्बत कार्यालय में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सांसदों और पार्टी के सदस्यों तक पहुँचने और कार्यक्रम के दौरान पत्रक और पुस्तकों के वितरण के लिए धन्यवाद दिया।

तिब्बत कार्यालय इस कार्यक्रम में शामिल होकर खुश है और अपने भविष्य के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए और अधिक तिब्बती युवाओं को प्रोत्साहित करता है।

• तिब्बत में 'नरसंहार' का चित्रण करती है ताइपे की प्रदर्शनी

taipeitimes.com, चेन यू-फू
२७ सितंबर २०२१

मध्य ताइपे के एक किताब की दुकान में २६ सितंबर से तिब्बत मुद्दे को लेकर शुरू हुई प्रदर्शनी में इस क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मानवाधिकारों के हनन पर प्रकाश डाला गया।

झोंगझेंग जिले में टू-यूट बुक्स में लगी प्रदर्शनी में तुंग चिंग द्वारा चारकोल रेखाचित्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें दलाई लामा, चीनी जेल में दिवंगत हो गए तिब्बती भिक्षु तेनज़िन डेलेक रिनपोछे और तिब्बत के समर्थन में वर्षों से मुखर रहे हैं हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेर सहित तिब्बती नेताओं और मानवाधिकार समर्थक कार्यकर्ताओं को दर्शाया गया है।
स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत-ताइवान के सदस्य तुंग ने कहा कि चीन सुनियोजित तरीके से तिब्बतियों पर अत्याचार करता है और उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति के बारे में शिक्षा तक पहुंच से वंचित करता है।

तुंग ने कहा कि एक तिब्बती मित्र ने एक बार उससे कहा था, 'मैं चीनी नागरिक बनने नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ तिब्बती बन कर रहना चाहती हूं।'
ताइवान में निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रतिनिधि केल्सांग ग्यालत्सेन बावा ने तिब्बत मुद्दे पर ध्यान देने के लिए ताइवान के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि चीन का तिब्बतियों पर अत्याचार उनकी संस्कृति को नष्ट करने और स्थानीय स्कूलों को बंद करने को लेकर है, जहां छात्र अपनी पृष्ठभूमि के बारे में जान सकते हैं।
तिब्बतियों को अपनी भाषा बोलने के लिए जेल में डाल दिया जाता है या अपने मोबाइल फोन पर दलाई लामा की तस्वीर रखने के लिए पीट-पीटकर मार डाला जाता है।उन्होंने इन उपायों को 'नरसंहार' कहा।
तिब्बत और ताइवान के लिए ह्यूमन राइट्स नेटवर्क और स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत-ताइवान द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी ०९ अक्तूबर तक चलेगी।

• तिब्बती प्रतिनिधि चीन के अत्याचारों के खिलाफ बहु-सांस्कृतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए

tibet.net, ३० सितंबर, २०२१

धर्मशाला। चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना दिवस से एक दिन पहले यानि ३० सितंबर को जर्मन संस्था 'वॉयस ऑफ यूरोप' और 'फेडरेशन फॉर ए डेमोक्रेटिक चाइना' ने संयुक्त रूप से 'ह्यूमनिटी एट ए क्रॉसरोड्स इन चाइना: ए मल्टी कल्चरल पुशबैक अगेंस्ट डिक्टेटरशिप (चीन में चौराहे पर मानवता- तानाशाही के खिलाफ बहु-सांस्कृतिक पलटाव)' विषय पर वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया।

केंद्रीय तिब्बत प्रशासन (सीटीए) की आधिकारिक चीनी वेबसाइट के प्रधान संपादक जयांग त्सेरिंग को पूर्वी तुर्केस्तान, दक्षिणी मंगोलिया, हांगकांग और ताइवान के प्रतिनिधियों के साथ संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।
सीटीए की ओर से जयांग त्सेरिंग ने चीनी सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ बोलने वाले प्रतिनिधियों के प्रति दृढ़ समर्थन व्यक्त किया और इस दौरान परम पावन दलाई लामा और सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग के मार्गदर्शन में चीन तक पहुंच बनाने से संबंधित गतिविधियों को जारी रखने के लिए सीटीए की प्रतिबद्धता से अवगत कराया।
जर्मनी में ताइवान के राजदूत प्रो. हसीह चिह-वेई ने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए ताइवान, तिब्बत, पूर्वी तुर्केस्तान, दक्षिणी मंगोलिया, हांगकांग और मुख्यभूमि चीन के लोगों के आग्रह पर जोर दिया। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उत्पीड़ित सभी समुदायों की एकता का भी आह्वान किया और उनसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया।
बाद में इस सेमिनार में कुएरबन हैयूर (वर्ल्ड उग्यूर कांग्रेस के बर्लिन प्रतिनिधि), श्री शी हैमिंग (पीपुल्स पार्टी ऑफ इनर मंगोलिया, कोलन के अध्यक्ष), तेनज़िन ज़ोचबाउर (तिब्बत इनिशिएटिव, बर्लिन के कार्यकारी निदेशक) और वांग गौक्सिंग (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर, फेडरेशन फॉर ए डेमोक्रेटिक चाइना, हेग) ने अपने भाषण दिए।
उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति और भाषा के विनाश, पर्यावरण के विनाश और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दमन पर प्रकाश डालते हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए।

सेमिनार के एजेंडे में, न्यू ज़ुर्चर ज़ितुंग के पत्रकार जुर्गन काहल, फ्रांसीसी साइनोलॉजिस्ट मैरी होल्ज़मैन, डसेलडोर्फ द फोर्थ जून मेमोरियल म्यूजियम इन हांगकांग के पत्रकार चांग पिंग, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स बर्लिन के पत्रकार माइकल लेह, वाशिंगटन डीसी के पत्रकार श्रीचिंग चेओंग, कोलन के लेखक/संपादक श्री पैन योंगझोंग, आईपीके-मीडिया वाशिंगटन डीसी के प्रमुख अन्ना वांग,

ताइपे में राजनीति शास्त्र के विद्वान प्रो. ज़ेंग जियानयुआन ने विभिन्न विषयों पर बात की और प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए।

पीआरसी की ७२वीं वर्षगांठ यानी ०१ अक्तूबर को आयोजकों ने जर्मनी में चीनी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। यह भी बताया गया कि जर्मनी के करीब दस मानवाधिकार संगठन भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे।

• चीन के शिकंजे से तिब्बत कब और कैसे मुक्त हो पाएगा?- ओप ऐड

eurasiareview.com
२६ सितंबर२०२१, एन.एस.वेंकटरमन

छह दशक से अधिक बीत चुके हैं, जब चीन ने सेना भेजकर तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया और विरोध करने वाले तिब्बतियों को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया था। इसके बाद दलाई लामा और उनके अनुयायियों के पास तिब्बत छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उधर, अब चीन तिब्बती क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाता जा रहा है। यह तिब्बत में चीनी मूल के लोगों को बसाने और तिब्बतियों की उस वर्तमान पीढ़ी का दिमाग बदलने के लिए व्यवस्थित रुप से उपाय कर रहा है, जिस पीढ़ी ने दलाई लामा को नहीं देखा है। कुल मिलाकर चीन तिब्बत के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है।

हालांकि, अब यह स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है कि चीन तिब्बती भावना को कुचलने में पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। यह इस तथ्य से और अधिक साबित होता है कि चीन किसी अन्य देश के नागरिकों को तिब्बत की यात्रा करने और इस महान बौद्ध क्षेत्र में अपने लिए परिस्थितियों को देखने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है, चीन के पास तिब्बत में दिखाने से कहीं अधिक छिपाने के लिए है। चीन अब लोहे के पर्दे से तिब्बत की रक्षा कर रहा है।
निर्वासित तिब्बतियों ने अपनी खुद की एक सरकार बनाई है और तिब्बत के साथ हुए अन्याय के बारे में लगातार आवाज उठा रहे हैं और चीन के आक्रामक नियंत्रण से तिब्बत की मुक्ति और स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। कई तिब्बती संघ लोकतांत्रिक देशों में कार्य कर रहे हैं। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि तिब्बत को मुक्त करने के लिए तिब्बतियों का रोना अरण्य रोदन बन कर रह गया है क्योंकि दुनिया ने कुल मिलाकर तिब्बत की दुर्दशा को नजरअंदाज कर दिया है।

भारत ने तिब्बतियों को रहने और अपनी सरकार चलाने के लिए जगह दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। एक बार अमेरिकी सरकार ने भी तिब्बतियों की दुर्दशा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है लेकिन इससे आगे कुछ नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी सरकार सोचती है कि अमेरिका में तिब्बती संघों को कार्य करने की स्वतंत्रता देना भी ही वर्तमान के लिए पर्याप्त है।
एक जमीनी सच्चाई यह है कि छह दशकों में मूल रुप से तिब्बत के कई तिब्बती परिवार दूसरे देशों में चले गए हैं और परिवारों के वंशज दूसरे देशों के नागरिक बन गए हैं। जबकि वे चीनी सरकार के हाथों तिब्बत द्वारा झेले गए अपमान के बारे में चिंतित हैं। वे इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं और हकीकत के विरुद्ध आशा करते हैं कि भविष्य में किसी समय कोई चमत्कार होगा जब तिब्बत को उसकी स्वतंत्रता और गौरव वापस मिल पाएगा। आज किसी को यकीन नहीं है कि ऐसा होगा और कैसे होगा या नहीं होगा।

१९६० के दशक में, जब चीन ने तिब्बत में प्रवेश किया तो भारत एक ऐसा देश था जो इसका विरोध कर सकता था और इसे चीनी सरकार का एक नाजायज कृत्य करार दे सकता था। दूसरी ओर, तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु, जो स्वयं एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, अपने कर्तव्य में विफल रहे और चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे को लगभग मंजूरी दे दी। बाद में, एक अनुभवी राजनेता के रुप में माने जानेवाले भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तिब्बत पर कब्जे के इस जले पर और नमक छिड़कते हुए चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे को आधिकारिक मंजूरी दे दी और तिब्बत के भाग्य को लगभग सील कर दिया।
इसलिए, इतिहास यह दर्ज करेगा कि चीन के अलावा भारत भी प्रमुख देश रहा है, जिसने चीनी आक्रमण पर चुप रहकर और तिब्बत पर चीन के अस्वीकार्य कब्जे के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति प्रदान करके तिब्बत के हितों के खिलाफ काम किया है। जब भारत ने इस तरह से कार्रवाई की तो दुनिया भी चुप रही। इस तरह तिब्बत को अकेला और तिब्बतियों को अकेले ही आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया गया।
अब समय आ गया है कि भारत को तिब्बत पर चीन के कब्जे को मंजूरी देने में अपनी ऐतिहासिक गलती का प्रायश्चित करना चाहिए।

आज भारत को चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का पूरा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और उसे अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बार- बार चीन के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। चीन भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपना होने का दावा करता है और उसने भारत की प्रगति को किसी भी तरह से नियंत्रित करने और रोकने की अपनी महत्वाकांक्षा को छुपाया नहीं है।
वर्तमान में चीन भारत को अपना प्रमुख शत्रु मानता है जबकि वह अमेरिका को अपना प्रतिद्वंदी मानता है। अफ़ग़ानिस्तान तालिबानों के नियंत्रण में है और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान और चीन एक साथ काम कर रहे हैं और इस्लामी आतंकवादी भारत को निशाना बना रहे हैं। भारत को चीन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़नी होगी।
भारतीय राजय अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजने के अलावा चीन ने पहले ही भारत को काफी नुकसान पहुंचा रखा है। ऐसी परिस्थितियों में, भारत का चीन को खुश करने या चीन के साथ शांति स्थापित की कोशिश करना बेकार और यहां तक कि अपमानजनक भी है।
तिब्बत पर चीन का कब्जा भारत के लिए एक बड़ा सैन्य खतरा है। यह ज्ञात तथ्य है कि चीन पहले से ही भारत को निशाना बनाकर तिब्बत में एक मजबूत सैन्य अड्डा बना रहा है।

अब, भारत के पास बिना किसी हीला-हवाली किए चीन के खिलाफ मुखर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसे चीन की आक्रामक क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को दुनिया की नजरों में बेनकाब करना होगा और दुनिया को इस बात का एहसास कराना चाहिए कि अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बावजूद चीन अब आर्थिक रुप से एशिया और अफ्रीका में अपने आकाश को सैन्य रुप से विस्तारित करने की अघोषित महत्वाकांक्षा के कारण शांति का खलनायक बन गया है।
भारत को चीन को उसकी औकात दिखानी होगी और चीन को बताना होगा कि भारत भी अब पीछे हटनेवाला नहीं है।
ऐसा करने का प्रभावी और एकमात्र तरीका निर्वासित तिब्बती सरकार को तिब्बत की वैध सरकार के रुप में मान्यता देना है। अगर भारत इस तरह बिल्ली के गले में घंटी बांध पाता है तो उसका मंतव्य निश्चित रुप से साफ हो जाएगा। संभवतः अमेरिका और उसके जैसे अन्य लोकतांत्रिक देश भी इसका अनुसरण करेंगे, यही तिब्बत के लिए अपनी मुक्ति और स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रारंभिक बिंदु होगा। जहां तक तिब्बती मुद्दे की बात है तो गेंद साफ तौर पर भारत के पाले में है।
वर्तमान में, कई देशों को चीन के इरादों और तरीकों के बारे में चिंता है और मुख्य रुप से चीन को मात देने के लिए देशों के बीच गठजोड़ बनाए जा रहे हैं। अभी लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने करने का समय आ गया है।

तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रुप में मान्यता देकर भारत चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षी

योजनाओं और रणनीतियों के आगे बढ़ने में एक मजबूत प्रतिरोध पैदा करेगा।
इस प्रक्रिया में, दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी क्योंकि दुनिया को तिब्बत की स्वतंत्रता और देश की गरिमा को बहाल करने और तिब्बत को वैश्विक क्षेत्र में उसका सही स्थान देने का अपना कर्तव्य निभाना होगा।
एन.एस. वेंकटरमन एक गैर-लाभकारी संगठन 'नंदिनी वॉयस फॉर द डिप्राइव्ड' के ट्रस्टी हैं। इस ट्रस्ट का उद्देश्य दलित और वंचित लोगों की समस्याओं को उजागर करना और उनके मुद्दे का समर्थन करना, निजी और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण तरीके से विचार-विमर्श करना है।

• भारत को अपनी तिब्बत नीति को 'मुक्त' करना चाहिए, 'दुनिया की छत' पर मानवाधिकारों के उल्लंघन को उठाना चाहिए

abplive.com, राहुल कश्यप, १४ सितंबर २०२१

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी ल्हासा में ०१ जून २०२१ को ऊंचाई वाले क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑफ-साइट स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के दौरान नागकू हाईस्कूल में पत्रकारों के सरकार द्वारा आयोजित यात्रा के अवसर पर तिब्बती छात्रों को स्कूल से छुट्टी के समय चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक विशाल पोस्टर के पास से गुजरते हुए दिखाया गया है।

१९५१ में दुनिया की छत पर धरती के सबसे शांतिपूर्ण लोगों पर एक त्रासदी टूट पड़ी थी। इस ग्रह के इतिहास में इसे विडंबना ही कही जाएगी कि सबसे क्रूर शासनों में से एक क्रूर शक्ति द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर इसे 'शांतिपूर्ण मुक्ति' की संज्ञा दी गई। इस कृत्य से शर्म भी शर्मसार हो गया होगा।
भारत और चीन दोनों का कई हजार साल पुराना सभ्यतागत इतिहास है, लेकिन लगभग ४००० किलोमीटर लंबी सीमा पर इन दोनों देशों के बीच कभी सीमाई साझेदारी नहीं रही।
तिब्बत पर कब्ज़ा करने और बहुसंख्यक बौद्धों के अधिकारों को कुचलने के बाद ही बीजिंग (तब पेकिंग) के साथ भारत को मजबूरी में सीमा साझा करनी पड़ रही है।

तिब्बती बौद्धों पर आक्रमण और उसके बाद की अधीनता इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है कि कैसे एक क्रूर माओवादी पार्टी-सरकार ने मूल निवासियों के मौलिक और प्राकृतिक अधिकारों पर कहर बरपाया।
यूएनएचसीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार, इतिहास के सबसे बुरे नरसंहारों में से एक में अकेले मार्च १९५९ और अक्तूबर १९६० के बीच ८७,००० से अधिक तिब्बती मारे गए। अट्ठानवे प्रतिशत मठों और भिक्षुणी विहारों को नष्ट कर दिया गया, और ९९ प्रतिशत भिक्षुओं और भिक्षुणियों को हटा दिया गया।
गलवान में संघर्ष की ताजा यादें और वहां से सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर चल रही बातचीत की कछुआ चाल के साथ, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस साल जुलाई में तिब्बत की हालिया यात्रा ने भारत में कई पंख कतर दिए हैं।
किसी राष्ट्रपति की ३० वर्षों में तिब्बत की पहली यात्रा भारत के लिए संदेशों से भरी हुई थी। यह यात्रा तिब्बत की राजधानी ल्हासा और अरुणाचल प्रदेश के नजदीक निंगची शहर के बीच बुलेट ट्रेन के उद्घाटन के तुरंत बाद हुई। इसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में बताया गया।
यात्रा के दौरान उन्होंने तिब्बत के विकास के बारे में बात की। हालांकि, तथ्य यह है कि कथित विकास ने तिब्बत के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है और यह भारत के लिए एक गंभीर खतरा भी है। विनाश की सीमा इतनी अधिक है कि जनसंहार के बाद कहा जाता है कि तिब्बत अब 'पारिस्थितिकी' का सामना कर रहा है।
'मेल्टडाउन इन तिब्बत: चाइनाज रेकलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स फ्रॉम द हाइलैंड्स ऑफ तिब्बत टू द डेल्टास ऑफ एशिया' पुस्तक में माइकल बकले लिखते हैं, 'तिब्बत की विशाल नदियों को चीनी इंजीनियरिंग कंसोर्टियम द्वारा सत्ता की खातिर मुख्य भूमि की प्यास बुझाने के लिए क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और चीन के औद्योगिक परिसर को आपूर्ति करने के लिए खनिजों की तलाश में भूमि का लगातार खनन किया जा रहा है।
अपनी चल रही १४वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपरी धारा) पर एक विशाल बांध को मंजूरी दे दी गई है, जिससे चीन के बारे में बहस शुरू हो गई है कि जल्द ही इस विशाल नदी के महान घाटी में जलविद्युत क्षमता शुरू हो जाएगी। इस बांध से हर साल ३०० अरब किलोवाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है।
भारत के लिए ब्रह्मपुत्र का बहुत महत्व है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह देश के मीठे पानी के संसाधनों का लगभग ३० प्रतिशत और इसकी कुल जलविद्युत क्षमता का ४४ प्रतिशत को पूरी करता है। कई नदियों के ऊपरी तटवर्ती देश चीन की स्थिति भारत की स्थिति को कमजोर बनाती है।
जबकि भारत ने ग्रैंड वेस्टर्न वाटर डायवर्जन प्रोजेक्ट (या शूओटियन कैनाल) और रेड फ्लैग रिवर प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन द्वारा नदी के पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर मोड़ने के बारे में कई बार अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है, लेकिन पहले से ही भारतीय सीमाओं के नजदीक तीन परियोजनाओं सहित ऊपरी इलाकों में छह जलविद्युत परियोजनाएं हैं।

तिब्बती पठार पर होने वाले पर्यावरणीय विनाश एक ऐसा विषय है जिसके बारे में वैश्विक समुदाय को चिंतित होना चाहिए। चीन के तिब्बत पर कब्जे का विरोध न करने की कीमत भारत अब भी चुका रहा है।
हम अक्सर भारत और चीन के बीच स्पष्ट अंता को भूल जाते हैं। हम एक संपन्न लोकतंत्र हैं जबकि चीन एक सत्तावादी पार्टी संचालित देश है। यह समझने वाली बात है कि इसीलिए भारत द्वारा लगातार न छेड़ने की कोशिश करने के बावजूद चीन ने स्पष्ट रूप से 'अमित्र' नीति अपनाई है। यह अमित्रता चाहे जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में लगू हो, या पूर्वोत्तर में विद्रोह को समर्थन प्रदान करना हो।
कम्युनिस्ट चीन के संस्थापक माओ-त्से-तुंग ने कहा था, 'तिब्बत वह हथेली है जिस पर अगर हम अधिकार कर लेते हैं तो फिर हम- लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश रूपी पांच अंगुलियों तक पहुंच जाएंगे।

तिब्बत पर चीनी कब्जे का विरोध न करने की कीमत भारत को चुकानी पड़ रही है, गलवान संघर्ष श्रृंखला में नवीनतम है। जबकि यह सूची लंबी है - २०१३ (चुमार), २०१४ (देप्सांग), २०१७ (डोकलाम) और १९६२ के आक्रमण को नहीं भूलना चाहिए। हालांकि, गलवान में किए गए दुस्साहस को मिले जवाब ने चीनी प्रतिष्ठान को आश्चर्यचकित कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह के संकल्प और पराक्रम के साथ उसके विस्तारवाद का डटकर मुकाबला करेगा। जबकि बीजिंग उन क्षेत्रों से हिलना नहीं चाहता है, जहां उसने अतिक्रमण किया है। इस बात की भी थोड़ी से आशंका है कि वह फिर से वही दुस्साहस करेगा। यह आशंका भारत की ओर से सैनिकों की भारी तैनाती के कारण हो रही है।
हालांकि, यह भी एक तथ्य है कि सैन्य गतिरोध को छोड़कर नई दिल्ली को अभी तक प्रतिरोध के सही भू-रणनीतिक उपकरण नहीं मिले हैं। तिब्बत कई लोगों के लिए एक 'कार्ड' हो सकता है, यह निश्चित रूप से एक ऐसा मुद्दा है जिसे भारत को सक्रिय रूप

से संभालने की आवश्यकता है।

इसलिए, यह उचित समय है कि भारत अपनी तिब्बत नीति पर फिर से विचार करे और निर्वासित तिब्बती सरकार को मान्यता दे। उसे तुरंत हिमालय की सीमा को भारत-तिब्बत सीमा कहना शुरू कर देना चाहिए। भारत को दृढ़ता से कहना चाहिए कि १९१४ में मैकमोहन रेखा की तिब्बत द्वारा पुष्टि की गई थी और उस समय चीन कहीं नहीं था।

इससे साबित होता है कि 'तिब्बत कम से कम स्वतंत्र देश था।'

तिब्बत पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का आधार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 'नरसंहार किए गए थे' और यह कि 'चीन द्वारा १९५१ में कब्जा किए जाने से पहले तिब्बत कम से कम एक स्वतंत्र देश तो था।'

तिब्बत से एक ही धार्मिक परंपरा से जुड़े भारत को तिब्बती लोगों की मित्रता और उनका समर्थन मिलता है, जिनके भारतीय इतिहास के साथ संपर्क जुड़े हुए हैं और बौद्ध धर्म के माध्यम से ऐतिहासिक संबंध हैं।

परम पावन दलाई लामा तिब्बत के समान ही भारत के पुत्र हैं।

पीछे मुड़कर देखें तो १९९५ में एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया था, 'असंतोष का दूसरा हालिया स्रोत तिब्बत में गैर-तिब्बती बसने वालों, मुख्य रूप से हान (चीनी नस्ल) और हुई (चीनी मुस्लिम अल्पसंख्यकों में से एक) की संख्या में भारी वृद्धि है। इनकी उपस्थिति को कई तिब्बतियों द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय पहचान के लिए खतरा माना जाता है। हान और हुई बसने वालों को आर्थिक खतरे के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि उनमें से कई दुकानें और जमीन खरीदने के लिए तिब्बत आते हैं।

चीनी दण्ड से मुक्ति, लोहे के पर्दे के पीछे अधिकारों के बेरहम उल्लंघन और चीन द्वारा वैश्विक चिंताओं की घोर अवहेलना की वास्तविक कहानियां तो तब सामने आएंगी जब तिब्बत वास्तव में मुक्त होगा और लोगों को लौह कठोर शासन का डर नहीं रहेगा। इस समय तिब्बती जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो दांव पर न लगा हो। इसे समझने के लिए इससे बेहतर तरीके से तुलना नहीं हो सकती है कि तिब्बतियों को उनके चीनी समकक्षों की तुलना में और भी कम नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।

जब पूरी दुनिया में मानवाधिकारों को सभी के लिए अपरिहार्य मौलिक अधिकारों के रूप में देखा जाता है, ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि चीनी पार्टी नियंत्रित शासन इसे 'अपनी शक्ति के अस्तित्व के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखता है'।

'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ने अपने 'प्रेस फ्रीडम इंडेक्स २०२०' में १८० देशों की सूची में चीन को १७७वें स्थान पर रखा है। तिब्बत में लौह घेरेबंदी की वास्तविकता यह है कि उत्तर कोरिया में तिब्बत से अधिक विदेशी पत्रकार आते-जाते रहते हैं और विदेशियों के आवागमन के मामले में तिब्बत इस स्टालिनवादी देश की तुलना में अधिक दुर्गम है।

मार्च २०२१ में आई फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भी तिब्बत को सीरिया के बाद सबसे कम मुक्त देश के रूप में वर्णित किया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस ने निर्वासित तिब्बती सरकार के हवाले से रिपोर्ट प्रकाशित किया है कि चीनी उत्पीड़न के विरोध में २००९ और २०१९ के बीच २६ महिलाओं सहित कम से कम १५४ तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया।

तिब्बत पर अमेरिकी नीति अब स्पष्ट है

भारत को स्वाभाविक रूप से इस मुद्दे पर नेतृत्व करना चाहिए था और बीजिंग के खिलाफ एक कूटनीतिक अभियान शुरू करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाये पिछले अक्तूबर में ४०पश्चिमी देशों ने अल्पसंख्यक समूहों के साथ दुर्व्यवहार के लिए चीन की निंदा की थी। तिब्बत पर अमेरिकी नीति अब स्पष्ट है और इसने मानवाधिकारों के हनन पर चीन से जवाबदेही दिखाने की मांग की है।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने वरिष्ठ चीनी राजनयिक यांग जिएची से बातचीत में इस मुद्दे को उठाया।

अमेरिका ने कंसोलिडेटेड एप्रोप्रिएशन ऐक्ट- २०२१ (समेकित विनियोग अधिनियम) पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि 'अमेरिकी विदेश मंत्री तिब्बत में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की निगरानी के लिए तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीन जनवादी गणराज्य, चेंगदू स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास का शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे।'

तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट ऐक्ट- २०२० की एक उपधारा में इस मांग में एक और चेतावनी है कि 'विदेश मंत्री अमेरिका में आगे तब तक चीन को किसी भी अन्य वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, जब तक कि तिब्बत के ल्हासा में अमेरिका का वाणिज्य दूतावास स्थापित नहीं हो जाता है।'

पिछले साल सितंबर में, चीन पर अमेरिकी कांग्रेस-कार्यकारी आयोग ने कहा था, 'चीनी सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बती बौद्ध धर्म का 'चीनीकरण' करने के लिए बड़ा अभियान चला रही हैं। वे तिब्बती धार्मिक संस्थानों और समुदायों को कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी नीतियों का समर्थन करने के लिए मजबूर कर रही हैं। चीनी अधिकारियों का दावा है कि उनके पास भविष्य के १५वें दलाई लामा सहित सभी धार्मिक हस्तियों के पुनर्जन्म को चयनित और चिह्नित करने का एकमात्र अधिकार है। उसने १९९५ से तिब्बत के दूसरे सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्व पंचेन लामा को गायब कर दिया था। इससे वह दुनिया के सबसे लंबे समय तक अज्ञातवास में रहने वाले कैदियों में से एक बन गए हैं।

अमेरिका की तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट ऐक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'तिब्बती बौद्ध धर्मगुरुओं के चयन, शिक्षण और पूजा के संबंध में निर्णय विशेष रूप से आध्यात्मिक मामले हैं जिन्हें तिब्बती बौद्ध परंपरा के भीतर तिब्बती बौद्ध धर्म के उचित धार्मिक अधिकारियों द्वारा और साधकों की खुद की इच्छा के अनुरूप ही किया जाना चाहिए।'

चीनी सरकार राजनीतिक आलोचना के प्रति असहनशीलता है जिस कारण हिंसा, मनमानी गिरफ्तारी, नजरबंदी और यातना की स्थिति आती है। प्रगतिशील आधुनिक दुनिया को यह जानकर नफरत होनी चाहिए कि चीनी सरकार 'सामाजिक आकलन प्रणाली' लागू कर रही है जिसके तहत व्यक्तियों के आकलन मूल्यांकन, उपभोक्ता व्यवहार, इंटरनेट उपयोग और आपराधिक रिकॉर्ड के आंकड़े एकत्र किया जाता है और अंत में नागरिकों को 'विश्वसनीयता' के संबंध में मूल्यांकन करता है।

इसलिए भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह तिब्बती मुद्दे का समर्थन करे, अपनी तिब्बत नीति पर फिर से विचार करे। चीन की नाराज़गी का अब कोई डर नहीं है। अमेरिका की स्थिति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सैन्य गठजोड़ 'क्वाड' का गठन, नई दिल्ली की स्थिति को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाता है, जो कि अब तक की मानसिकता के ठीक उलट है।

(राहुल कश्यप पूर्व पत्रकार हैं। वह सार्वजनिक मामलों और अंतरराष्ट्रीय संबंध के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं।)

(अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर विभिन्न लेखकों और मंच के प्रतिभागियों द्वारा व्यक्त की गई राय, विश्वास और विचार उनके व्यक्तिगत हैं और वे एबीपी न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के विचारों, विश्वासों और विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।)

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Jigmey Tsultrim
Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

जिगमे त्सुलट्रिम
समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोनः 011–29830578, 29840968
ई–मेलः indiatibet7@gmail.com

सांसद श्रीमती केरी मैकार्थी के साथ तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री सोनम त्सेरिंग फ्रासी।

आईटीसीओ और तिब्बत समर्थक समूहों के प्रतिनिधिमंडल के साथ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू